missed the bus. But I hope and pray that my Prime Minister, with his far sight, with his compassion and with his desire to settle things, will resume the dialogue as early as possible, enlist the help of those who want permanent peace between India and Pakistan and resolve this problem before, Sir, you quit office or quit this world. Thank you.

FALICITATIONS TO THE INDIAN CRICKET WORLD TEAM

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : महोदय, देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने न केवल ट्राई-सीरिज फाइनल आज आस्ट्रेलिया की धरती पर जीती है, बल्कि भारत अंडर-नाइंटीन मैच में भी विश्व कप जीता है। तो इन दोनों के लिए मैं सदन में प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि हम भारतीय टीम चाहे अंडर नाइंटीन जूनियर टीम हो, चाहे सीनियर टीम हो, क्योंकि उसने विश्व चैम्पियन आस्ट्रेलिया को हराया है, तो दोनों को यह सदन बधाई दे। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, यहां मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि वे एक मिनट में कोई संदेश इस मामले में दे सकें और टीम को बधाई दे सकें तो सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत है।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am sure, all Members of this august House will join me in sending our warmest congratulations to all those cricket players who have done our country immensely proud. What they have achieved is an indication of the great potential in the world of sports that exists in our country. Given good leadership, good management, this country can excel in other sports as well.

SHRI RAM JETHMALANI (Nominated): Sir, the President's Address should contain a reference to our sportsmen.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—(Contd.)

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा) : बहुत-बहुत शुक्रिया उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का टाइम दिया है। अभी प्रधान मंत्री जी ने हमारी क्रिकेट टीम के सदस्यों को आज की जीत पर बधाई दी है, हम सब उसमे शामिल हैं। लेकिन आज जिस विषय पर बहस हो रही है, वह है प्रेजिडेंट एड्रेस और मुझे यह कहना है कि प्रेजिडेंट एड्रेस में कामनवैल्थ गेम्स का जिक्र किया गया है। भारत सरकार कामनवैल्थ गेम्स को कामयाब करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं भी खेलों के संघ से वाबस्ता हूं। यह सबको पता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृपा से कामनवैल्थ गेम्स इंडिया को अलाट हुआ।

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

जब वह प्रधान मंत्री जी थे, तो उन्होंने एक ब्लैंक चैक की तरह इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन को सपोर्ट दी कि ये गेम्स इंडिया में आयें। आज स्थिति यह है कि इंडियन ओलम्पिक संघ एक तरफ है और भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक तरफ है। इनमें एक तरह से लड़ाई हो रही है और प्रधान मंत्री जी इसको चुपचाप देख रहे हैं और हालत यहां तक पहुंची है कि बैडमिंटन चैम्पियनशिप इंडिया में होनी थी, वह कैंसिल हुई, इसलिए कि उनको शटल कॉक नहीं मिले। शूटिंग चैम्पियनशिप में हमें वर्ल्ड मैडल आने की उम्मीद है, उनके पास एम्युनिशन नहीं हैं। मेरी ये सारी बातें रिकार्ड पर आ चुकी हैं। मैं हाउस में डिप्टी चेयरमैन साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कामनवैल्थ गेम्स इंडिया की प्रेस्टीज़ है, किसी इगो प्राब्लम से, किसी इंडिव्युजल प्राब्लम से पूरी सपोर्ट गेम्स को नहीं देंगे और जितनी ओलम्पिक कमेटीज़ और फेडरेशन्स हैं, उन सब को हिदायत दी जाये, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकें।

दूसरी बात यह है, अभी श्री राम जेठमलानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेजिडेंट एड्रेस में यह बात कही गयी कि हम पड़ोसी देशों से भी बहुत अच्छी बात करें। सर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री

जी, अभी उठकर चले गये। माननीय होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं और यह उनके दायरे में आता है। हमने बहुत कुछ किया कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती हो। यह बहुत अच्छी बात है कि वहां पर डेमोक्रेसी से नई सरकार आ रही है। शायद होम मिनिस्टर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री उपसभापति : आप बोलिए।

श्री तरलोचन सिंह : सर, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की दोस्ती के लिए वह एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं और वह स्टेप यह है कि जो भी आदमी, औरत 1947 से पहले पैदा हुए हैं, वह इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गये हैं, जो 1947 से पहले पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और माइग्रेट होकर इंडिया में आये हैं, वह जेनरेशन खत्म हो रही है। 1947 से आज 2008 है, आप वन टाइम एक ऐलान करिए कि जो भी इंडिया से पाकिस्तान गया है और वह 1947 से पहले पैदा हुआ है, उसको स्पेशल परमिट दीजिए कि वह अपने घर में आकर अपने घर को एक बार देख जाये। हर इंसान यह चाहता है कि वह अपनी बर्थ प्लेस को देखे और मरने से पहले हर आदमी एक यात्रा अपनी बर्थ प्लेस पर करना चाहता है। अगर आप यह स्टेप लेंगे, तो अच्छा रहेगा। जो लोग 1947 से पहले पैदा हुए हैं और जिंदा हैं, वे आपको दुआएं देंगे और वे अपनी फैमिली को दिखायेंगे कि हम कहां पैदा हुए। जब मुशर्रफ साहब आये थे, तो आप उनको दिल्ली में दरियागंज की हवेली में ले गये कि यह उनका बर्थ प्लेस है। ऐसा हर कोई चाहता है, अगर आप यह स्टेप लेंगे, तो इंडिया-पाकिस्तान की दोस्ती में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा।

सर, प्रेजिडेंट एड्रेस में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कई बातें मिसिंग हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ साल पहले एक कांस्टीट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया गया था और जस्टिस वैंकटचलैय्या, फारमर चीफ जस्टिस आफ इंडिया उसके चेयरमैन थे। उस कमीशन में बहुत बड़े-बड़े लीगल एक्सपर्ट्स डाले गए। उस कमीशन ने दो साल तक सारे इंडिया में घूमकर एक रिपोर्ट दी कि कांस्टीट्यूशन में क्या-क्या अमेंडमेंट्स किए जाएं। लेकिन हमें हैरानगी है कि उस रिपोर्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई, आज वह रिपोर्ट कहां है? इसका पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी रिपोर्ट को सरकार ने कहां और किस जगह बंद कर रखा है। उस रिपोर्ट में एक रेकमेंडेशन यह थी कि सैक्शन -25 ऑफ इंडियन कांस्टीट्यूशन, इसमें उन्होंने एक माइनर अमेंडमेंट प्रपोज की, जिसका बेनिफिट कई कौमों को होता है, not to the individual, because section-25 चाहता है, हिन्दू that is, सिख, पारसी एंड बुद्धिस्ट, तो कमीशन ने कहा कि यह बात गलत है क्योंकि इसका गलत मतलब निकलता है। उन्होंने कहा कि आप इसमें कॉमा डाल दो— हिन्दू, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन। इससे यह होगा कि सारे धर्म बराबर होंगे। अब इतनी छोटी सी अमेंडमेंट से आज जैन कौम को, सिखों को और बुद्धिस्टों को यह हक देते हैं कि वे इंडिपेंडेंट कौमें हैं। अब इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जैन कौम वाले हर जगह से आते हैं और कहते हैं कि क्यों हमें सैक्शन-25 में बंद कर रखा है? सिखों की डिमांड भी बहुत दिनों से चल रही है और अभी तक सरकार इस बात को लिए बैठी है तथा इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि एटलीस्ट अगर और कमेटी की रिपोर्ट नहीं तो इस अमेंडमेंट को लाया जाए। जैन कम्युनिटी को जो बाकी हकूक मिलने हैं, वे भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको सैक्शन-25 में इंडिपेंडेंट नहीं किया गया है।

सर, जब श्री नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेशनल माइनोरिटी कमीशन की स्थापना पार्लियामेंट्री एक्ट 92 में की, क्योंकि कमीशन तो पहले मोरारजी देसाई के टाइम में बना था, लेकिन पार्लियामेंट्री एक्ट 1992 में बना। उसमें यह फैसला हुआ कि मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और पारसी पांच कौमें हैं, जो कि नेशनल मॉइनोरटीज में हैं। ये मॉइनोरिटीज सारे भारत में होंगी। अभी एक नई चर्चा छिड़ी है कि बजाय नेशनल के इनको स्टेट एलॉट किया जाए। मैं बड़ा हैरान हूं कि जो नेशनल मॉइनोरिटीज़ डिक्लेयर हो चुकी हैं और पार्लियामेंट के एक्ट से हैं, तो अब उसको कैसे बदला जा रहा है। सभी कम्युनिटीज की तरफ से आवाज उठ रही है कि इसको स्टेट लेवल पर न किया जाए और नेशनल लेवल पर रखा जाए, वरना इसके बड़े गलत परिणाम होंगे। आज आप स्टेट में कह रहे हो और कल आप डिस्ट्रिक्ट में करोगे। इससे इंडिया और डिवाइड होगा, तो इसके लिए यह नेशनल एक्ट यही रखा जाए।

सर, एक बात अभी सरकार ने की है कि आपने ओवरसीज़ इंडियंज के लिए एक मिनिस्ट्री बनाकर एक बड़ा

ही अच्छा कदम उठाया है। जो NRI और पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजन बाहर रहते हैं, उनको बहुत सहूलियतें दी हैं। मैंने पिछले साल एक क्वेश्चन डाला था, तो उसका जवाब यह दिया गया कि 87 ऐसे इंडियन NRI जिनके पास वैलिड वीजा था, वे दिल्ली एयर पोर्ट से वापस कर दिए गए। वे वीजा लेकर आए थे, लेकिन इमिग्रेशन ने उनको अंदर नहीं आने दिया। इसका कारण पूछने पर पता चला कि जो कम्प्यूटर इमिग्रेशन में था, जब उनको वीजा दिया गया तो उसमें उनकी एन्ट्री नहीं थी। आप सोचिए कि जो आदमी अमेरिका, कनाडा से टिकट लेकर यहां आ रहा है और उसके पास वैलिड वीजा भी है, उसको वापस करके उसको कितनी मेंटल परेशानी हुई होगी और फिर उनको वापस भेजकर उनका कितना नुकसान हुआ होगा। यह बड़ी हैरानगी की बात है कि जब आप NRIs को इंडिया ही नहीं आने देते हैं, तो फिर सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है? मैंने सुना है कि एक ब्लैक लिस्ट है ।... (**समय की घंटी**)... जिसका उस ब्लैक लिस्ट में नाम पड़ गया उसको वीजा नहीं दिया जाएगा। इसलिए सरकार इस बारे में जरूर कुछ करे।

सर, जैसे अभी बात चली है, मैं इस बात को मानता हूं कि जो शैड्यूल्ड कॉस्ट है, यह मज़हब के नाम डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि शैड्यूल्ड कॉस्ट सब के लिए बराबर है। चाहे वह सिख है, ईसाई है, चाहे मुसलमान है या हिन्दू है, यह सबको मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि सिखों को राइट दिया है। मैं कहता हूं कि सिखों को राइट सिर्फ पंजाब में दिया है। अगर पंजाब से बाहर कोई दलित सिख है, तो उसको कोई राइट नहीं है। यह बड़ी हैरानगी है कि अगर कोई दलित सिख पंजाब से बाहर है तो उसको कोई राइट नहीं है। जो कानून में खामियां हैं, इनको पूरा किया जाए और यह राइट सभी जगह दिया जाए।

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Shri Buta Singh contested from Punjab.

श्री तरलोचन सिंह : सर, यह राइट सिक्ख को ऑल इंडिया नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। एक बंजारा कौम है, जो सारे इंडिया में फैली है। वे करोड़ों लोग हैं, उनको हर स्टेट में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। Why don't we list them under Banjara all over country? उनको शैड्यूल्ड ट्राइब में लिया जाए और सभी सहूलियतें दी जाएं।

सर, मैंने इस हाउस में पिछले साल भी रेज़ किया था और अब मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम नेशनल लीडर का सत्कार करते हैं। अभी भारत सरकार ने श्री जगजीवन राम का बहुत अच्छा सत्कार किया है। आपने कहा कि उनका घर जहां है, वहां उनके नाम का स्मारक बने। यह अच्छा है, परंतु जब चौधरी देवी लाल का नाम आता है तो सरकार चुप हो जाती है। यह जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है, यह हमें समझ नहीं आई है। यह बात मैं दोहरा रहा हूं। क्योंकि चौधरी देवी लाल इंडिया के दो बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। आज आप लोन की, फार्मर की बात कर रहे हो, इंडिया में यह श्रेय उनको जाता है। अगर पहली बार किसानों का किसी ने कर्ज माफ़ किया तो चौधरी देवी लाल जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हर फार्मर को दस हजार रुपए की छूट दी थी। उस वक्त यह नहीं किया था कि छोटा फार्मर है या बड़ा फार्मर है। दस हजार रुपए की छूट चौधरी देवी लाल ने दी और इतने बड़े लीडर को, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उनके मकान, जिसमें वे रहे, जहां उनकी डेथ हुई, वहां उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी आयडियोलाजी आपके साथ नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है कि सरकार पिक एंड चूज की पॉलिसी छोड़े और इस काम को करे।

सर, ऐसा ही एक इश्यू है कि हमारे जो स्टेट स्टेच्यूट्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, यह नेशनल है, स्टेट में है। लेकिन यह देखा गया है कि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट बदल जाए, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट आए तो कमीशन मैम्बर, जो पहले चले आ रहे हैं, उनको निकाल तो सकते नहीं हैं, उनका काम बंद कर देते हैं। वे काम नहीं करेंगे। उनसे सरकारें काम छीनकर, कोई कमेटी बनाती है। सर, इसकी तरफ देखा जाए।

सरकार का यह जो फिफ्टीन प्वाइंट प्रोग्राम है...(**व्यवधान**)...मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। इस फिफ्टीन प्वाइंट प्रोग्राम को, मैं इसे एप्रिशिएट करता हूं, यह माइनोरिटीज के लिए है। सर, यह बहुत हैरानगी है कि सभी माइनोरिटीज हैं, लेकिन इसमें आप माइनोरिटीज को डिवाइड क्यों कर रहे हो। यह माइनोरिटीज छोटी

हैं। एक लाख पारसी हैं, पौने दो करोड़ सिक्ख हैं, ढाई करोड़ क्रिश्चियन हैं, आप उन्हें डिनाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को सभी कुछ मिले, लेकिन बाकी माइनोरिटीज को इग्नोर न किया जाए। बाकियों में भी इतनी ही गरीबी है, जितनी इनमें है। सभी को पूरा हक मिले और आप इसे डिवाइड करने की कोशिश न करें।

इसी तरह से माइनोरिटीज लैंग्वेजेस हैं। सरकार ने माइनोरिटी लैंग्वेज के लिए हर जगह कमीशन बना रखा है, लेकिन यह देखा गया है, मैंने ही कई बार रेज किया है, जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज़ है, हरियाणा तथा हिमाचल पंजाब से निकले हैं, लेकिन वहां पर पंजाबी लैंग्वेज बंद है। कोई पंजाबी टीचर नहीं है, हालांकि दोनों पंजाब के हिस्से थे। यहां यह कम्पल्सरी थी, लेकिन आज कोई पंजाबी लैंग्वेज का टीचर नहीं है और कोई पंजाबी सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार रोज कहती है कि हम माइनोरिटी लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं।

सर, मैं लास्ट प्वाइंट कहना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने साठ हजार करोड़ रुपए का बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के बयान आने शुरू हो गए हैं। सरकार को इसे रिव्यू करना पड़ेगा कि इसमें बहुत कुछ कमी है। अभी आज एक ही बयान आया है। हमारे चौधरी संपत सिंह, जो हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं; एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप ओवर ड्यू माफ़ कर रहे हैं, ड्यूज कहां गए? ओवर ड्यू वह है, जिस बहाने बैंक का कर्ज वापिस ना दिया हो, रह गया हो, आप वह दे रहे हो। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार इसके लिए कोई कमेटी स्थापित करे। आज प्रकाश सिंह बादल का भी बयान आया कि बहुत लीस्ट बेनेफिट हमें मिलने वाला है। इन बातों पर आप जरूर गौर कीजिए।

सर, एक प्वाइंट कश्मीरी माइग्रेन्ट्स का हैं। जो कश्मीर से निकलकर आ गए, उन बेचारों का क्या कसूर है? वे कहीं घूम रहे हैं, अपने देश में ही रिफ्यूजी हैं। सरकार ने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, वे अपने घरों से ही बाहर बैठे हैं। एक वे कश्मीरी, जो उस पाकिस्तान से जम्मू में बैठे हैं। उनको भी रिफ्यूजी स्टेटस ही नहीं दिया गया है। यह कहा गया है कि वह कश्मीर हमारा है, परंतु वह कश्मीर हमारे पास नहीं आना है। हम सुलह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब पाकिस्तान से आकर बैठे हैं, उन्हें भी रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए।

मैं ज्यादा नहीं कहता, आपके हुक्म से ये बातें कहकर बैठता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. I am in the same predicament as Mr. Jethmalani was. Mr. Siddiqui spoke his heart, so is Mr. Sengupta who spoke what I wanted to say about — rural and urban divide — and Ms. Bhartia spoke about education and a little thunder was also stolen by Mr. Jethmalaniji who spoke about communalism. But, I cannot match him, because he spoke in the light of and by entering into the philosophy of Islam which I thought, as a student of philosophy, that I should rather say this on the floor of this House. Today, I hope that I am not mistaken, because we have been treated to a good political rhetoric, good idiomatic thunders and sometimes with factual blunders. Mr. Dhawan was saying, that it was necessary that we criticise, but 'condemnation', as Pt. Jawaharlal Nehru said, for everything that was being presented to you will lead you to nothing but a nullity and meaninglessness. It makes even the father of cynicism hide his face so much so what exactly is the character of any House or a wise man to criticise a particular proposition which crosses the line of criticism and enters the field of cynicism, we lose not only perspectives but to get into fractured perspectives. I hope we understand that the Address before us is a very sacred Address. It is not a progress report that the Head of the country is placing before you. To say that it lacks direction, to say that it is insipid, उसमें जोर नहीं था, जैसा कि बहुत सीनियर मैम्बर जनेश्वर मिश्र साहब ने बताया, to say that it did not contain anything at all, really shocks me because what more do you want in this country after 60 years, where, we the people of India, gave unto ourselves a Constitution

of equality and freedom, which only, as Mr. Sengupta and some of you were saying, was monopolised or exploited by a section. And, what were rich and poor in those days still continues. Rich becoming richer was first and poor becoming poorer the second day; and benefits not percolating down was the third day; and, now, Rs. 22 versus 36 families the fourth day. At that particular time, when you are trying to come to grips with the situation; when you are trying to know what exactly the society is made of; when you are trying to talk of the world, you have really tried to borrow about inclusiveness, even communism, of which you are trying to talk, is not religion, it is inclusiveness. When we are talking of minority, welfare, it is inclusiveness. This inclusiveness, which you had introduced some five years back, meant economic inclusiveness. For the first time, I am so happy, the House should also be happy that this inclusiveness, today, includes the social inclusiveness because without social justice, without taking into consideration all the people the inclusiveness would never fructify. And, as Mr. Jethmalani says, the father of Foreign Policy is Mahatma Gandhiji. The economic philosophy of this country, the new era of politics that Dr. Manmohan Singh wants to herald is, again, based on Gandhism, and nothing at all. A man who looks to the last man in the last rung is inclusiveness, that is percolating down. That is what we are trying to achieve. So, let Mr. Yechury, who finds fault with our architecture, know that this architecture is a design, is a game plan, a concrete game plan, as Senguptaji has said, to lead us to every corner of the country, every section of the people, so that the economic fruits, the promise of social justice, the promise of equality and freedom reaches every section. That exactly is new era of politics into which we are entering into, thanks to the UPA Government. I am not speaking because I belong to a party that is a member of the UPA Government. But I am speaking on behalf of the people, who have been looking to you all through that when you said that benefit was not percolating down, when Rajiv Gandhi said that only 10 paise reaches and 90 paise are taken away. Now, we are trying to build the programmes and systems.

Sir, with this, I say that we have a direction, it is a vision document. I am not saying that it has given all the details. I am also not trying to go into the economics of it because tomorrow you will be debating the Budget, where you will certainly debate the details of the Budget. And, you will also be having the Ministerial demands, where you will be discussing the details thereof. When Shri Dwivedi initiated the debate, he raised a very pertinent point, which should touch every heart of ours. Joshiji and everybody referred to it. I think, Sir, you will give time to this House to discuss why the values in public life are falling so fast. Why the politicians are being degraded? Why is this profession becoming a disrespectful profession although there cannot be a greater or sacred profession than public life? We have left everything. Many of us might have done good in ather fields. We could have been better academicians or bureaucrats if we wanted. We had gone nearer to people to understand them. Gone are the days when the khadi clad man used to be looked at with all kind of reverence and respect. Today it has become a brand label of nothing but a corrupt and criminal person. Why is this happening? A debate is necessary because four or five senior members suggested it. I am not going into it. But I can only tell you that a politician is not one who has come out from the firmament. A politician is one who gets evolved from the society. When there was no school in my village, I went and shouted for it and I became a social worker. When I did not get the school, I went and collected the signatures of people and I became a public worker. The same social worker got evolved into a public worker. When I did not get it, I contested for a Sarpanch to get that school and became a political worker. So, every politician inherits as social urge and comes out with some kind of

an idea, some kind of a feeling, some kind of attachment and some kind of absolute passion for social service and social work. Then, are we being looked down upon? This is one thing which we should look into.

Sir, the Address before us is one where you can evaluate. It is not for accountability, but, nonetheless, there is scope for criticism. Agriculture continues to be the Archilles' heel for the Indian economy. In spite of all the best we could do, in spite of Rs. 25,000/- crores given to it, and now Rs. 37,000 crores have been given to it, yet, everybody has a complaint, a grouse or a grievance on that field. It has therefore to be revisited. It has to be looked into. But there is promise in it. In all our programmes that are given to us, we have some kind of hope.

Shri Sitaram Yechuryji said that we are giving outside support to the Government. I am happy he has given outside support. The CPI (M) Members are here. I am looking to then. Let this outside support remain for ever despite their differences. If that is there, it will be very ...(*Interruptions*)... One of my colleagues, Shri Singhvi, quoted a U.S. President who said that yesterday has gone, let us look to tomorrow. Whether it is yesterday or tomorrow, we in this party or this UPA Government with your outside support will be futurist. It looks ahead, but from the pad which is now grounded today. Yet based on the technology of yesterday. So, the three period have been taken in. That exactly leads us to inclusive governance. What exactly is this inclusive governance? In a country of our size; perhaps, the largest democracy in the world, today it is ruled by a handful few. Sixty or seventy Ministers take all the decisions. Although we talk of decentralisation of administration and governance, I don't think much progress has been made as we cherished it to be. So, this is one area where although we have been talking for the last many decades, much needs to go down the ground and start ruling the roost.

Sir, we are trying to talk about the values in governance. I will go to these values. I am touching Panchayati Raj institutions and decentralisation which brings good governance. Mr. Singhvi gave you 12 points as to what is good governance ...(*Time-bell*)... Sir, is the time over? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you. We have to conclude this debate and there are still ten participants. So, please stick to the time.

DR. K. KESHAVA RAO: Had I known the time limit, I would not have started my speech. With all humility, I am submitting to you that I blame myself for it. I stayed for too long in the Legislature. Had I been here, I would have been in the list of seniors ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to tell the Members that we have fixed the time for the debate. It is an important debate. Sixteen hours have been fixed. We have to complete it. Tomorrow at 3 o'clock the reply by the Prime Minister is fixed. We have to conclude within that time. I need your cooperation; otherwise, how can we...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: No, No, Sir. I totally agree with you. I am submitting myself to you. If you had told me the time, I would have kept that in mind. Otherwise, I say "all right."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, each Party is allocated some time. It is there.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, how much time has been allocated to me?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is ten minutes.

DR. K. KESHAVA RAO: So, ten minutes are over then.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have a digital watch with me.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, that is what I am saying. If you want me to sit, I would sit down.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I request you to give me ten minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude in two minutes.

DR. K. KESHAVA RAO: Okay, Sir.

Sir, somebody was challenging our track record. Mr. Jaitley was talking about our track record. He was trying to say that economy has come to a standstill. Has a country which is today the second fastest growing economy in the world come to a standstill? I think I should look back to the dictionary or thesaurus to know what exactly the word "standstill" means. Somebody said, "you are slow". In another decade, Mr. Deputy Chairman, Sir, we are going to be the third largest economy of the world, next to Japan. Sir, our growth rate has grown from 3.5 per cent to 9.1 per cent, three times of what it was some years ago. Show me one country which has achieved this much of growth rate, except China. Sir, investment to the tune of 35 per cent of the GDP, which is the world's highest investment, has come here. How has it come in? What is the industrial climate today? Everybody wants to invest here. The climate is getting brightened day by day. I admit that as far as agriculture is concerned, something needs to be done. But this much of investment followed by matched savings itself shows that surplus money is created in the domestic market. As far as prices are concerned, it is true that everybody is concerned about it. But what exactly are the prices you are trying to talk about? In a world economy, in the WTO regime, ours is the only successful country which has been able to insulate our prices from that of the prices in the world markets. I am not saying that we have done well, but we have done better than many other people, of which we should feel proud. What have we done? The inflation rate is being maintained at 4.6 or 4.7 from that of 6 per cent. I am not saying that all of us are satisfied about it, but the growth, the rate, the efforts, the measures that we are trying to take need a fullthroated support, if not a total support, to us, internally, if not from outside.

Sir, as a student of economics, Mr. Jaitley said, "statistics is fudgy maths. According to him there are three kinds of lie - lies, damn lies and statistics." But all through his 40 minutes' speech, he kept quoting statistics; I don't know why, for fudgy maths or for better maths? What I am trying to say is, let us have a right perspective.

Sir, as for internal Security and terrorism, nobody in this House would like us to have a soft policy on terrorism. Nobody in this House, or, in this country would think that violence should have any place violence has no place in democracy. Every one of us has talked about naxalism. I am sure you would not mistake me that naxalism in Andhra Pradesh, has been curbed by 70 per cent, not because of the gun, it is not because of the military or it is not because of the police. I have been in the Party, I have been in the Government, I have had the privilege of talking to the naxalites' representatives who refused to talk to elected representatives because they consider this Government as a collaborative Government. They know that I am one of those who is totally opposed to any kind of violence, even the violence of a gun or even a violence of the tongue. They joined the peace talks and we had a 6 months peace. What did we do when talks broke? Within one year, we distributed 4.7 lakh acres of land which they had put in the agenda, though left us, without discussing that. What did we do? When the talks broke, as the President of the Party took out Gandhi Shanti Sandesh Yatra and went into the naxalite forests. And went into the Naxalite forests. It is not that I went there and talks began there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Keshava Raoji, please conclude.

DR. K. KESHAVA RAO: So, we had gone there. So, what is necessary today is, we need to evolve a measure, a policy, a strategy that can start a political dialogue and, at the same time, we have to be stern as far as the law and order is concerned. In addition to this, we also have to get into the economics. When you say that it is a socio-economic problem, try to understand what is the social milieu which you are trying to talk, what exactly are the economics which you are trying to talk. So, these three things need to be packaged together properly so that we can face this, counter this with some kind of a well thought-out strategy. Sir, we need to take into confidence all political parties, all public men and the people who know the social realities , particularly, of the rural areas and tribal areas. Thank you very much.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Sir, on behalf of our party, All India Forward Bloc, I rise to extend my support to the Motion of Thanks on the President's Address, of course, with serious reservations on some important issues.

Sir, the hon. President's Address sounds like a Nightingale singing at a lofty height in the air, having no touch with reality. And, this phenomenon is particularly evident when we hear her saying that the Government is committed to 'inclusive growth'. All the economic growth that the Government could achieve during the last four years is exclusively for about 15 per cent of our population whom Netaji Subhash Chandra Bose described as the 'haves' of the society, depriving the majority 85 per cent 'have-nots' of the society. The growing economic disparity between the 'haves' and 'have-nots' of the society cannot be covered up under the rosy publicising of about nine per cent GDP growth. While 77 per cent of our population live on Rs. 20 per day, India occupies a proud position among the first ten billionaires of the world. While the profitability of the corporate houses are steadily going up, about 35 per cent of our population are still living below the poverty line. Unfortunately, this reality has not been reflected in the President's Address. Until and unless the pro-capitalist economic policy of the Government is changed, the aforesaid stark reality will continue to haunt us. The recent Human Development Report for 2007-08 released by the UNDP ranked India 128 out of 177 countries, working it out through measures of life expectancy, education and income. The President's Address is silent on this point.

The other serious aspects missing from the President's Address include price-rise, growing inflation and unemployment. The skyrocketing prices of essential commodities, including foodgrains, are hitting hard millions of poor people. Once Jawaharlal Nehru vowed to hang the blackmarketeers publicly, although never practised in reality, but even any such intended declaration does not come from the present Congress leadership. In spite of repeated requests, the Government does not show any interest to ban forward marketing of 24 listed items. And on the other hand, the public distribution system is being weakened gradually. With jobless growth of industry and declining agricultural sector, the employment situation is posing a serious threat to the new generation. It has no mention in the President's Address. But the Address has enthusiastically mentioned about the Special Economic Zones promoted by the Government. In reality, the SEZs, in the name of employment generation and export development, are actually creating a privileged class and a country within the country, threatening the livelihood of millions of poor farmers. SEZs are the biggest land-grab measure in recent times. It is as much harmful as was the policy of disinvestment of the NDA Government. An equally serious condition prevails in the agriculture sector. Its growth rate has declined to about 2.6 per cent. The growth in production of foodgrains has declined from 5.2 per cent in 2005-06 to only 0.9 per cent in 2007-08. It threatens our food security, compelling the country to depend more and more on the import

of wheat and other foodgrains, which reminds us about the dark age of PL480. Simultaneously, the condition of our farmers, who constitute about 70 per cent of our population, has also been worsened. As a result of this, debt trapped farmers are committing suicide every thirty minutes. The Government has allowed this situation to continue for four years and has now come out with a debt-waiver scheme amounting to Rs. 60,000 crores. But it is apprehended that this costly scheme will not be able to solve the problem at all. About 40 per cent of the farmers who take loans from the interest-hungry private moneylenders will be left out of the purview of these huge funds whose source has also not been explained yet.

Sir, internal security is also a matter of serious concern. The President's Address could not give any positive direction for tackling it on an urgent basis. As has already been said by many of the hon. Members, it is most unfortunate that the Government has failed to move the Women's Reservation Bill even in four years. We pledge our support to the cause of women's reservation.

Lastly, I would like to mention about the hon. President's hope that the Civil Nuclear Cooperation with the USA will become possible. The matter has already been debated in the Parliament elaborately. When the majority of Members of both Houses of Parliament have expressed their concern and opposition to the Indo-US Nuclear Deal, if the Government still insists on going ahead with operationalising the deal, it would be acting against the sense of the House. For the sake of democracy, and for honouring the majority opinion of Parliament, we hope the Government will desist from proceeding further in the matter.

Thank you, Sir.

SHRI RAHUL BAJAJ (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman Sir, I rise to support the Motion of Thanks that has been presented. The President's Address has been an over-arching review of the economy and many other issues. I whole-heartedly support the desire of not only the Government, but also of the Opposition parties and all of us, to have growth, growth and more growth, and that the growth has to be inclusive. I had been hearing some of the friends on the Left and the Right. I speak as an Independent, of course. We have done a lot in the last four years. By and large, I don't think that anybody is disputing that. But a man like me doesn't get satisfied with that. We don't pat ourselves on the back just for that. We see the world. Where is the world, the developed world, the US, the Europe, China and South-East Asia? And we want to catch up. Our per capita income is US 900 dollars per annum. We have heard 30 per cent or 40 per cent people who live on Rs.40 a day. Arjun Sengupta's Report said that 70 per cent people in unorganised sector live on Rs.20 a day. It is something of which we Indians cannot be proud. We have to hang our heads in shame, Mr. Deputy Chairman. So, I am not looking at the glass which is half full. There is lot that has been done in the last four years and in the previous Government. In fact, since 1991 the momentum is carrying us forward. I am looking at the half empty glass. I want to fill that up and fill it in a manner in which, to the extent possible, it helps the bottom 30 per cent of our people and not only the billionaires to which Sitaram Yechury*ji* and my friend Shri Barun*ji* referred. We can take care of billionaires. They are few in numbers. But we have to take care of 300 or 400 million Indians. Sir, I find still tremendous waste of Government resources. Again, this has been discussed enough because delivery and implementation in our Government system is very poor. Out of Rs.100, as Rajiv Gandhiji said, only Rs. 16 reaches the intended beneficiaries. गरीब के पास 16 रुपए पहुंचते हैं, 18 पहुंचते हैं, 25 पहुंचते हैं, 70, 80, 90 नहीं पहुंचते हैं। It is because of the administration cost, salary cost, inefficiency and corruption and, unfortunately, tremendous corruption. And, there I say repeatedly that we

need the private sector. Some of my friends here do not like two words 'private sector'. We want more public-private partnership. We have seen the examples of Telecommunications took place and Civil Aviation. Wherever you brought in the private sector, the cost went down, faster growth took place and better services to the citizens of India. Civil Aviation and Telecommunications are good examples. Through you, Mr. Deputy Chairman, I request the Government, Home Minister was here, now the Industry Minister is here, to bring in more and more areas in private sector. I am not against the foreign private sector but I say, at least, the Indian private sector. We are as patriotic and as nationalistic as anyone else. No more, but no less. Sir, I believe in the last few years whether it was the coalition *dharma*, whether it was my friends in the Left, whatever the reasons, the opportunity for reforms has been missed. For four years, some reform has taken place. The Government will tell us हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ। I will tell them यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ। इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, पावर नहीं है, लेबर पॉलिसी अभी भी तकलीफ में है और I am pro-labour, but इम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, प्रॉपर इम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। We could see Government trying. But somebody or other in the coalition partners or other friends in the Left said, No, this is capitalistic; this should not be done. We have done well in the last ten years. This is due to the people of India, the farmers of India, the industrialists of India and the entrepreneurs of India, yes, with the support of the Government. Government have supported us. But let us not forget, Mr. Deputy Chairman, that the momentum which was built up carrying us forward should not lull us into a false sense of security. We are already experiencing reduced rates of growth from 9.4 per cent or 9.6 per cent last year. The Government's own figures say that this year it may be 8.6 per cent. Industrial growth rate, संतोष मोहन देव जी, बहुत कम हो गया। November-December 2007, 5 per cent and 7 per cent, and November-December 2006, 13 per cent and 15 per cent. I am surprised लोग बात नहीं कर रहे इसके बारे में। एग्रीकल्चर में 65 प्रतिशत है, दुनिया में, डेवलपड् वर्ल्ड में 3 या 4 परसैंट है, हमारे यहां 3-4 नहीं होगा, पर 60-65 तो नहीं रह सकता for 30 years. It will come down to 50, 40, 30 per cent, not three per cent. So, thirty per cent people will go out. How many people are there? Three hundred million people are there. How will you give them *naukri* or self-employment? Service sector and industrial sector are there. For industrial sector, we need power; we need infrastructure; we need a pro-industry policy which, I think, this Government wants to do, but their hands are tied. Employment has to be created because where will the agriculturist go? We have heard enough about agriculturist in India. He is in serious problem. The rate of growth has gone down. Ultimately, like an industry, whatever I sell, for example, if I sell a motorcycle, the price should be more than my total cost. It is simple. मेरी total cost से मेरा selling price ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो मैं अपना लोन भी repay नहीं कर पाऊंगा और आपको मेरा लोन भी माफ करना पड़ेगा। किसान का भी जो produce है, चाहे cotton है, चाहे wheat है, उसका दाम कैसे मिलेगा, यह बताने से पहले आप मेरे लिए घंटी बजा दोगे।

श्री रुद्रनारायण पाणि : आपका price, total cost of production से कितना ज्यादा होना चाहिए?

श्री राहुल बजाज : 2 परसेंट, 5 परसेंट, 10 परसेंट आप फिक्स कर दो, यह matter of detail है, total cost 100 है, profit 200-300 नहीं है। 100 के ऊपर यदि 100 परसेंट profit है, तो वह profit नहीं है, वह profiteering है, उसको पकड़ो । लेकिन competition के ज़माने वह profit रह नहीं सकता, discounting हो रही है । आप अलग से मेरे से बात कर लीजिए। सोशलिज्म में monopoly थी, बजाज चेतक का 10 साल का delivery period था, वह मनचाहा price charge कर सकता था, नहीं करता था, इसलिए ब्लैक था, आज नहीं कर सकता, आज वह Platina के लिए, Xede bike के लिए मनचाहा price charge नहीं कर सकता, क्योंकि TVS है, Suzuki है, Hero Honda है। इसके लिए कोई ज्यादा profit

नहीं है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता but, there are sectors like tyre and some other sectors where there is a shortage. जहां shortage है, वहां you can have higher prices.

श्री उपसभापति : मार्केटिंग हो रही है।

SHRI RAHUL BAJAJ: So, Sir, it is not politically acceptable, लेकिन अगर farmer को कमाई करनी है, तो irrigation ज्यादा करना पड़ेगा। गुजरात में 40 परसेंट irrigation है for cotton farmers, वह suicide नहीं करता। बाजू में विदर्भ में 4 परसेंट irrigation है for cotton farmers, वह suicide कर रहे हैं। अब जो land holding की बात है, यह एक् एकड़, दो हैक्टेयर से कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया को देखिए और 5-10-20 हैक्टेयर जाने दीजिए। आपने जो सिस्टम 60 साल से चलाया है, उसकी वजह से किसान मर रहे हैं। एक दिन वे politician को मारेंगे... **(व्यवधान)**...

सुश्री मैबल रिबैलो : क्या आप marginal farmers को employment देंगे?

श्री राहुल बजाज : मैबल जी, आप झारखंड में जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, तब बात करूंगा। अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं उनसे बहुत डरता हूं ... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : समय कम है, आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। आप डिस्टर्ब करेंगे, तो ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा।

श्री राहुल बजाज : अभी हमारे एक मित्र बरुण जी ने बोला, उनको पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज पर अपने मित्र राम जेठमलानी जी से agree करता हूं। मैं तो बहुत conscious हूं sovereignty के लिए। हिंदुस्तान को sovereignty नहीं छोड़नी चाहिए। 100 करोड़ लोग ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हमको छोड़ने के नाम से डरना भी नहीं चाहिए। क्या हम कोई छोटे-मोटे देश हैं इधर-उधर के? हां, agreement करोगे, तो give-and-take होगा और अमेरिका बड़ा जोरदार देश है, बहुत बड़ा देश है। कुछ give-and-take होगा, लेकिन हमें अपने देश के लिए energy security चाहिए, इतनी पावर चाहिए। I am supporting the nuclear deal. The Government should go ahead. The Government should have guts to go ahead, as Shri Ram Jethmalani said, with or without consensus. With consensus, there is no problem; without consensus, the Government should go to the people - the bigger parliament. अब पाणि साहब भी ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। अब Strobe Talbott ने बोल दिया, ठीक है यशवंत सिन्हा ने deny कर दिया, पर ये लोग साथ में हैं, खाली left तकलीफ में है। ये लोग साथ में हैं, पर क्या करें, हां नहीं बोल सकते, अंदर-अंदर से साथ हैं, बाहर से नहीं हैं।

चीन के बारे में देखिए, इन्होंने जो कहा कि 93,000 स्क्वेयर किलोमीटर territory एक बात है, कोई बोल सकता है कि 1962 की बात भूल जाओ, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन territory तो वापस चाहिए। छोड़िए इस बात को। आज वह market economy नहीं है, WTO compliant नहीं है, उसका cost structure opaque है, हमको चीन से free trade agreement करना नहीं है। दुनिया में करे, खुद का फायदा देखकर करे, लेकिन मेरे हिसाब से चीन के साथ free trade agreement करने में हिंदुस्तान का बहुत नुकसान होगा। मैंने एक आर्टिकल में *Economic Times* में लिखकर गवर्नमेंट से पूछा था कि आप हमारी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं या Chinese industry के लिए काम कर रहे हैं? आप हमारी गवर्नमेंट हैं या उनकी गवर्नमेंट हैं। साथ ही साथ हमको देखना है कि दुनिया भर से जो raw materials हमको लेने हैं, China सब जगह से ले रहा है। China से मित्रता करनी है, झगड़ा नहीं करना है, वह बहुत बड़ा देश है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया में चीन पावरफुल देश है, मैं तो बोलता हूँ कि लालच से, influence से, सब तरीके से iron ore ले रहा है, यह ले रहा है, वह सब कुछ ले रहा है। इसलिए दाम बढ़ रहे थे। इसलिए हमारा inflation हो रहा है, crude oil का होगा, फ्रूट प्रोडक्ट्स का होगा, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का होगा, वह हमारे लिए डेंजर है। मेरे को लगता है कि 2008-09 में ग्रोथ और स्लो होगी और inflation बढ़ सकता है for reasons beyond the control of Reserve Bank of India. China से खुद का interest देखकर मित्रता करनी चाहिए। China looks after its interests very strongly. We do not know how strongly they fight for their interests. America also fights for its interests very strongly. We must also fight for our interests very strongly.

Mr. Deputy Chairman, I come to my last two points. Good governance सब हमारी political parties ने, I am sorry to say, छोड़ दिया है। वोट चाहिए, वोट लेना कोई नुकसान थोड़े ही है, खराब बात थोड़े ही है, डेमोक्रेसी में वोट चाहिए। We need votes, but not at the cost of integrity, not at the cost of honesty, not at the cost of good governance. If you lose good governance, you are not taking care of the *aam aadmi*. बोलने को आम आदमी की बात करते हो, बाद में यह डील करते हो, वह डील करते हो, दुकान खोलकर रखते हो, सुनने में आता है हमको, मालूम नहीं है हमको, corruption की बात करते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट में नहीं, यह सब गवर्नमेंट में है, कितना corruption है, मैं as an industrialist बोल रहा हूँ, कोई देता है, कोई लेता है, यह बात ठीक नहीं है और यह populism कब आती है। Mr. Deputy Chairman, populism उन देशों में आती है where the governing elite, Mr. Chairman, has lost its credibility with the people...(*Interruptions*)...

श्रीमती जया बच्चन : सर, यह लेना-देना allowed है।

श्री राहुल बजाज : Sorry, मैं जया जी से माफी मांग लूंगा।

श्री उपसभापति : देना-लेना क्या है, यह explain करना पड़ेगा, देना-लेना ठीक है।

श्री राहुल बजाज : नहीं तो उसको आप expunge कर दीजिएगा, जया जी को पसंद नहीं है तो I withdraw it. हमारे मित्र हैं, हमारी बहुत मित्रता है। I do not know. मैं तो नया मैम्बर हूँ।

So, where the governing elite, Mr. Deputy Chairman, loses credibility with the people, loses trust of the people, then, it goes for populism. We are not far from such a situation. So, Mr. Deputy Chairman, in conclusion, I would only say that in spite of all this, in spite of poor governance, because of the innate strength, wisdom and integrity of the Indian people, our nation will continue to march ahead.

Change has come; more change will come. Most of the people leading the change, however, are outside the Parliament and most of them are outside the Government. These people who are leading the change, Mr. Deputy Chairman, believe in India, our nation, believe in themselves, and, they believe in *Satyamave Jayate*. Thank you.

KUMARI NIRMALA DESHPANDE (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, let me thank many of my friends who referred to Mahatma Gandhi and also the need to follow him.

While coming to the President's Address — many have referred to it — I would like to refer to a very catchy word, 'inclusive growth'. But I won't speak more on that because my friend, Dr. Arjun Kumar Sengupta, has already explained how that can be achieved. We have a long way to go to make the growth really inclusive. I would like to speak mainly on one problem, namely, internal security. The President has referred to two threats, that is, terrorism and left extremism. Yes, we are really facing those threats, which are trying to create a serious problem for India. But, I would just like to say one thing. If what the scientist does, if one method fails, you adopt another method. My friend, Shri Jethmalaniji, referred to Pakistan, I agree with him. I would just like to tell that when we were asked in one of our visits to Pakistan as to what is the solution for Kashmir problem, it just came out, maybe from me or my other delegate friend, गोली नहीं, बोली चाहिए। You can't solve any problem by violence or by bullets. You have to start a dialogue. I would like to humbly submit that for solving these two problems of terrorism and left extremism, whatever name you may give to it, the bullet has failed. You may go on increasing police force, giving them most modern equipment, sending Army and all that. Those problems can never be solved by this method. So, why can't we explore some other method, that is, dialogue?

The hon. President has also referred to Mahatma Gandhi's birthday being observed as International Day of Non-Violence by the whole world and accepted by every nation of the United Nations. We are proud of it. But, have we ever thought of trying this method of non-violence in solving these serious problems of terrorism and left extremism? Why can't we try it? Why can't we give a trial to that? Other methods have failed. Anybody can prophesise that it is bound to fail. You can never solve that problem by increasing the Armed Forces or by police or by this or that. You can never. So, why not start the new process. Let's go to the root of the cause. Why is there terrorism? There are some causes. Why does a young man become terrorist? What is the reason? Let us find out the reason. Why people join the left extremist movements? There are some reasons. We all know, there is lot of injustice in our society. The poor have to suffer on every front. We know that the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, especially we are working with those people in forest areas where our so-called Naxalite friends are also working, are there. Why do people are attracted to that way of life? Because there is disparity, poverty, hunger, injustice, etc. So, unless these causes are removed, these problems can never be tackled. Why can't the States, the civil societies, the Gandhians and all kinds of social activists think of applying non-violence to solve these problems? And, on the basis of my experience, I can say that non-violence knows no failure. We have not yet faced any failure in any endeavour that we have taken.

I would also like to refer to the hon. President's Address about our noble resolve of having good relations with both Pakistan and China. We had recently been to China. Some of our friends of the House were with us. What did we find? Something which is never reported. My friend, Mr. Naik is here. In every meeting, we met top leaders. They said our friendship is of two thousand years old. Yes, there were some aberrations. They are bound to be there, in 2000 years' history; there were small aberrations like 1962, but the friendship is 2000 years-old. Are we not going to take this plus point and build friendship on that? When we talked about tourism, Mr. Naik said, "When you come to India, you must visit Goa. It is a very beautiful place." The other friend said, "You must come to South India." So, that leader, who was hosting dinner for us said, "There are many places in India, there are many places in China, but there is only one place of Lord Buddha, that is, Bodh Gaya, and Bodh Gaya is our Mecca." We were simply surprised that in every meeting, the Chinese leader referred Bodh Gaya as their Mecca, and as every Muslim wants to visit Mecca, especially during Haj, every Chinese wants to visit Bodh Gaya. Have you ever given any attention to this plus point? Well, there is reference to 'Incredible India' in the President's speech. Yes, India is really incredible. You will not find such a place on the globe which has such a variety, which has such a diversity. So, it can be the best place for tourist attraction. But, I would like to point out one thing. Have we done anything worthwhile to develop Bodh Gaya, Rajgir, Nalanda, the whole Buddhist area to promote tourism? There is no direct flight from Shanghai or Beijing to Bodh Gaya. The hon. Minister, Shri Praful Patel said that we are building the Gaya Airport, making it international one. When? How much time are you going to take? It is not just China. China, Japan, Korea, the whole of South East Asia, we will get literally lakhs and lakhs of tourists, who will come with folded hands to visit India, and also increase the revenue. So, both ways, it is helpful. And I would again like to repeat that if we can plan our policy on 2000 years' friendship and develop the Buddhist places, then other problems that we are facing, will slowly get solved. They are very small problems. I would also like to refer to Pakistan, and I agree with Mr. Jethmalani that we in India have lost a golden opportunity to resolve the Kashmir issue. Anyway, better late than never. Let us again start the peace process. That issue is going to be solved. Whosoever may be the Government, the people of Pakistan want peace, they want good relations with

India, they are so friendly, and it is for anybody to go and see. Why can't we solve this problem? There is a reference to SAARC in the President's speech. Can we not think of making SAARC something like South Asian Union as we find the European Union, where Germany and France had fought two world wars in a short span of 50 years? Now, they are members of the European Union. Can't we think on those lines to make SAARC something like a South Asian Union and that may be able to help all the countries of this region?

Last, but not the least, I would like to say that India is the biggest country in every way in the South Asian Region, and our neighbours, who are small in every respect, they feel that they can't tolerate the big brotherly attitude of India many times. Let us do some heart searching. We have seen as peace activists, sometimes, big brotherly attitude taken by India. So, let us not be big brother, but just a brother of every country. Yes, people say India is becoming a super power. May I humbly submit that that is not India's dream and should never be a dream? India will be a friend of all, and, what Lord Buddha said, a *Kalyan Mitra*; not a Guru, but a *Kalyan Mitra*. Let us work for the welfare of all; let us be a friend of all. That is India's philosophy. We do not want to dominate any country. We do not want that our writ should run anywhere. We do not want to be even Gurus. We want to be friends and *Kalyan Mitras* of all the countries of the world. Let us forget about becoming a super power. That concept of becoming a super power and dominating the world is an old-fashioned concept. The world is changing; people are changing. We should also change our mindsets and be true Indians by praying for the welfare of all as the ancient *rishis* used to say. There was some reference to whether these people can live in that state. That is too small a problem. Our vision has always been the welfare of all. No Indian saint or *sufi* or *rishi* has ever prayed for his own community, his own State, his own language group or his own religion. They have always prayed for the welfare of the whole world.

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया,

सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत,

जय जगत।

Jai Jagat. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा (पंजाब) : थैंक्यू चेयरमेन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जेठमलानी जी की बात की ताईद करता हूं। मैं देख रहा था, क्योंकि यह पोइंट मेरे पास था, लेकिन वे पहले बोल गए। मैं काफी समय से देख रहा था, इस पर किसी ने बात नहीं की। कहीं भी पॉपुलेशन की बात पर कोई डिसकसन नहीं हुआ है और न ही इस पर प्रेज़ीडेंट एड्रेस में कोई चर्चा है कि फैमिली प्लानिंग पर कितना काम हुआ और इसके रिजल्ट अच्छे हैं, बुरे हैं, इसका कहीं भी कोई रिफ्रेंस उसमें नहीं है। सही बात है कि जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती, चाहे जितना मरजी काम-कर लो, जितना मरजी इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, जो मरजी कर लो उसका वही रिजल्ट रहेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने चाइना की बात कही, वहां जीरो ग्रोथ है। इसलिए उनकी प्रोग्रेस भी हुई है। दूसरा, किसानों की बात है क्योंकि 70 परसेंट लोग किसानी पर निर्भर हैं या किसानी का काम करते हैं। मैं यहां यह इसलिए भी देना चाहता हूं, क्योंकि इस पर काफी बातें हो चुकी हैं। 60 हजार करोड़ का लोन माफ किया गया है। एक बात स्पष्ट है कि इससे किसानों का बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला है। आज ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर श्री प्रकाश सिंह बादल की स्टेटमेंट है। पंजाब में बारह सौ करोड़ रुपए से ज्यादा माफ नहीं हुए। टोटल कब्जा जो पंजाब का है, उसमें 38 परसेंट से ज्यादा लोगों को उसका फायदा नहीं हुआ। उसके कई कारण हैं। अभी तो उसमें यह क्लिअर नहीं है कि वे इसमें 5 एकड़ मालिकी की बात करते हैं या जो जमीन काश्त करता है, उसको मिलेगा। पंजाब में ऐसी जमीनें हैं जो एन0आर0आइज0 की

हैं। वे खुद खेती नहीं करते, बल्कि उसको ठेके पर देते हैं, किराए पर देते हैं। तो इसमें उस फार्मर का नुकसान हुआ है, जो खेती करता है। उसको हम कैसे एकॉमोडेट करेंगे। दूसरे, साहूकारों की बात की है, वह ठीक है। पंजाब में बहुत से किसान ऐसे हैं, जिन पर ज्यादा लोन साहूकारों का है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि कर्जा माफ करने से किसानों का बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला। आज कर्जा माफ हो जाएगा तो कल क्या करेंगे, क्योंकि कर्जा तो फिर भी लिया जाएगा। हम जब तक बेसिक प्राब्लम हल नहीं करते, उस वक्त तक कोई भला नहीं हो सकता। बेसिक प्राब्लम क्या है ? बेसिक प्राब्लम यही है कि जब तक हम उसकी कास्ट को प्राइस से नहीं जोड़ते, एमएसपी से नही जोड़ते, उस पर वह कास्ट देकर नहीं लगाते, तब तक उसको कोई फायदा नहीं हो सकता । अभी बजाज साहब ने ठीक कहा है कि हर कोई अपनी कीमत तय करता है। इतनी मेरी कास्ट आयी, यह मेरा रेट है, चाहे आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ या किसी और के पास चले जाओ। हम अक्सर बात करते हैं - किसान कहता है कि मैं तो गन्ना फैंककर आया हूं, मैं तो धान को छोड़ आया हूं, फैंक आया हूं, हम बेच नहीं रहे हैं, हम फैंक रहे हैं, यह हमारी बदकिस्मती है। उसके लिए दो-तीन चीजों की जरूरत है। उन्होंने एक बात कही है कि छोटे फारमर की बहुत बड़ी प्राब्लम है - आज दुनिया के साथ कम्पिटिशन है। मैं यह नहीं कहता कि छोटा फारमर खत्म हो या छोटा फारमर खेती नहीं करेगा। हमारे यहां 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, जबकि दुनिया में कोई पांच प्रतिशत खेती करता है, कोई दस प्रतिशत खेती करता है। हमारा प्रेशर एग्रीकल्चर पर है। हमारे यहां जरूरत क्या है, छोटे फारमर के लिए कोआपरेटिव फार्मिंग पर जोर देना चाहिए। हमारे यहां वह शुरू हुआ है, कई स्टेटों में ऐसा हुआ है, लेकिन वह इतना प्रफुल्लित नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए या वैसे फार्म बड़े कराने चाहिए, तभी आउट-पुट बढ़ेगी, उसकी इन्कम तभी होगी, जब उसका दायरा बढ़ेगा, वह रिकगनाइज करेगा, वह कम्पिटिशन में आयेगा और तभी उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। एक तो खेत का जो किसान है, वह तो अपने खेत की पैदावार मार्केट में नहीं लाता है, वह देश को कुछ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका अपना गुजारा ही नहीं हो पाता है, तो वह क्या कॉमन पूल में करेगा। ये बेसिक प्राब्लम्स हैं, उसके डायवरसिफिकेशन की जरूरत है। डायवरसिफिकेशन के लिए भी बड़ी प्राब्लम्स हैं। हम कहते हैं कि फ्लोरिकल्चर करो, हार्टिकल्चर करो, जब लोग करते हैं, तो उसकी प्राइस पहले फिक्स नहीं होती है। उसके पहले प्राइस फिक्स करो, फिर उसको सब्सिडाइज करो, उनको गवर्नमेंट नये टेक्नीक सेंटर ऐड करे, लोगों की इन्कम बढ़ेगी। इसके साथ एक काम और करने की जरूरत है, वह यह है कि उसके साइड बिजनेस होना चाहिए, संबंधित कारोबार उसके होने चाहिए। डेयरी फार्म को एनकरेज किया जाये, पाल्ट्री फार्म को एनकरेज किया जाये, फिशरीज़ को किया जाये, फ्लोरिकल्चर को किया जाये, हार्टिकल्चर को किया जाये, उसको दूसरे संबंधित धंधों से इन्कम हो, तभी उसकी आर्थिक हालत बढ़िया हो सकती है।

सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की कुछ और प्राब्लम भी हैं, हो सकता है कि देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसी प्राब्लम हो। हमारी बार्डर स्टेट है। वहां बार्डर पर तार लगी हुई है। तार के पास पाकिस्तान की तरफ किसानों की जमीन है, उनकी प्राब्लम यह है कि उनको गेट से परमिट करते हैं, फिर उनकी तलाशी ली जाती है और उनको चार-पांच घंटे ही काम के लिए अलाउ किया जाता है। चार-पांच घंटे में किसान क्या काम करेगा, क्या कमाई करेगा, उनका कसूर क्या है ? उनका यही कसूर है कि वे बार्डर पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, जब भी हमारी पाकिस्तान से कभी लड़ाई हुई, उन लोगों ने फौज की मदद की है। वे उजड़े, उनके घर उजड़ गये, उनके घर कच्चे हैं, गांव में कोई पक्का घर नहीं मिलेगा। हमने पक्के मकान बनाने के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्या पक्के मकान बनायें, चार-पांच साल में कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है, कभी मिलिट्री आकर टेक-ओवर कर लेती है, कभी माइन्स लगा देते हैं। यह उनकी समस्या है। पहले उनको चार हजार प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था इसलिए कि इनका नुकसान हो रहा है, वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। वे कैसे करेंगे ? यह प्राब्लम बंगाल में भी होगी और स्टेटों में भी होगी, इसको भी ठीक करना चाहिए। किसानों की जो जमीन है, उसको ले लो, या जो तार के पार जमीन है, उनको पूरा कम्पनसेट करके कहीं और ले जाओ, उसको आप डिफेंस परपज़ के लिए रख लीजिए, जिससे कि किसान वहां पर अच्छी तरह से रह सकें।

एक और प्राब्लम हमारे यहां चल रही है। वह क्या है, सरहंद फीडर, राजस्थान कैनाल फीडर, दो बड़ी नहरें जो हैं, उनमें से एक हरीके नहर, पट्टी तहसील से निकलती है और एक नंगल से निकलती है। वे नहरें हरियाणा और राजस्थान को फीड करती हैं। उनका पानी जाता है, उनकी लाइनिंग बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनकी कभी रिपेयरिंग नहीं हुयी, उनकी सीपेज़ के कारण पंजाब की जमीन बर्बाद हो रही है, जिसको वाटर लागिंग कहते हैं, वह हो गयी है, लोगों की जमीन बेकार है, पंजाब का किसान क्या करेगा ? उसकी नई लाइनें डाली जानी चाहिए। उसको पंजाब मेंटेन नहीं कर सकता, वह तो सैन्टर मूवमेंट का काम है और उसको वह ऐड करे तथा नहरों का इंतजाम किया जाए। ऐसी जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। रेट ऑफ इन्टरेस्ट किसानों पर चार पर्सेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह किसान की आज की प्राब्लम नही है। हम कब से सुन रहे हैं शहीद-ए-आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी गाया करते थे 'पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। लुट गया माल तेरा'। हम उस समय से देख रहे हैं और आज भी वही हाल है। आज जरूरत है किसान को बचाने की । अगर हिंदुस्तान मे किसान बचता है तो हिन्दुस्तान भी तरक्की करेगा और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। आज पंजाब 50 पर्सेंट अनाज केन्द्रीय भंडार को देता है फिर भी पंजाब में सूसाइड होते हैं, तो यह प्रोब्लम देखने की जरूरत है। सर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि आज किसानी को बचाना बहुत जरूरी है। अगर बाहर से कणक 1600 रुपए की आती है, हमे 1500 ही दे दो तो मैं गारंटी से कहता हूं कि अकेला पंजाब ही आपके भंडार भर देगा और आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह हमारा वायदा है। कई और मसले हैं, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आखिरी प्वाइंट बोलिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : सर, एक बात और किसानों से संबंधित है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान आदि सभी राज्यों की सब्जी इस मंडी में आती है। हमें यह देख कर बड़ी हैरानी होती है, हमारे पंजाब में तो कहीं नहीं और बाकी स्टेटों का मुझे पता नहीं, किसान पर कहीं भी आढ़त नहीं है, वहां 6 पर्सेंट आढ़त ली जाती है। यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल पास है। कभी सैंट्रल वालों का ख्याल नहीं किया और दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आप कभी उसको चैक तो करें। वहां पर किसान की सबसे ज्यादा लूट होती है। ...**(समय की घंटी)**...मैं एक-दो और प्वाइंट रखना चाहता हूं। मैं इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने जो हिमाचल की आर्थिक सहायता की है, उत्तरांचल की है, जे.एंड के. की सहायता की है, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट सबसे ज्यादा सफरर हैं। उनको कई पैकेज मिले हैं और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से और भी कई रियायतें मिली हैं। पंजाब की इंडस्ट्री यहां से उजड़कर उन स्टेटों में जा रही है, हमारा क्या कसूर है? हमें खुशी है, वे हमारे पड़ौसी हैं, आप उनको भी डेवलप करो, लेकिन पंजाब, हरियाणा तथा और स्टेटों का भी ख्याल करो। जो इंडस्ट्रियल कोरिडोर है, उसको मुम्बई से दिल्ली अप-टू लुधियाना तक बढ़ाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बाजवा जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : एक्सटेंशन ऑफ रेल फ्रेट कॉरिडोर को...**(व्यवधान)**... लुधियाना तक करना चाहिए। पैरा-55 में आर्म्ड फोर्सेज़ के वैलफेयर की बात कही गई है। मैं यहां पर हाउस को बताना चाहूंगा कि यह इतनी खतरनाक बात है कि आर्मी में आफिसर्स भर्ती नहीं हो रहे हैं। वहां पर आफिसर्स की 30 पर्सेंट शोर्टेज है। उनको इतनी टेंशन है और उन पर इतना प्रैशर है, जिसके कारण हमारी फौज़ में डी-मॉलाइजेशन हो रही है। जो अच्छे जवान हैं तथा जो 700, 800 आफिसर्स हैं, वे प्री-मिच्योयर रिटायरमेंट लेकर जा रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**. यह बहुत सोचने की बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : और नहीं...**(व्यवधान)**... आप सिफारिश मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : यहां वे पक्ष हैं और वहां हम रूलिंग हैं। ...**(व्यवधान)**... वे हमारे भाई हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप अपनी पार्टी के वक्ता को with draw करा लीजिए, मैं समय दे दूंगा। ...**(व्यवधान)** ..

एक सम्मानित सदस्य : सर, वे बाजवा जी के क्लासमेट्स हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं? **(व्यवधान)...**

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : सर, पैरा-35 में सिविल एविएशन की बात है। उसमें बहुत तरक्की हुई है। हमें बहुत खुशी है। हमने मुम्बई देखा, बैंग्लोर देखा, वहां पर अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, बहुत बढ़िया बात है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भी पंजाब की प्रॉब्लम है। आदमपुर एयरपोर्ट है, एयरफोर्स बेस्ड है, मेरे सारे दोस्त कह चुके हैं कि अगर वहां पर सिविल एविएशन की फ्लाइट अलाऊ करें, वहां हमारे जहाज जा सकें, उसे दोआबा रिजन बोलते हैं, वह सेंटर है, 80% परसेंट पंजाब के लोग उस रिजन से आते हैं, जिनका एक घंटा, आधा घंटा टाइम लगता है, अगर वहां अलाऊ कर दिया जाए, क्योंकि बाकी सभी एयरफोर्स स्टेशन्स पर फ्लाइट्स अलाउड हैं, वहां यह कर दिया जाए तो यह इकॉनॉमिकली भी ठीक होगा और बाकी जो...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बाकी बजट में बोलिएगा। अब खत्म कीजिए। आप बजट में बोल सकते हैं...**(व्यवधान)**...

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करता हूं। यह पैरा 49 में है। यह बहुत बुरी बात है। जैसाकि बाकी भाइयों ने कहा कि जो मुंबई में हुआ, राज ठाकरे जी की जो बात है, यह खतरे की घंटी है। हम यह चाहते हैं...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बाजवा जी बैठिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरह का वहां व्यवहार किया गया, अगर हर स्टेट में यह हो जाए तो ठीक नहीं होगा। हमारे पंजाब में लोग यू.पी. से आते हैं, बिहार से आते हैं, हमारी इकॉनॉमी उन लोगों पर डिपेंड है। हम उनका वेलकम करते हैं। हमारे पंजाब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संबंध में मेरी कुछ सजेशन्स हैं। यह क्या तरीका है कि आप हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते, आप राजस्थान में जमीन नहीं खरीद सकते, आप जे.एण्ड के. में जमीन नहीं खरीद सकते, हमारे यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं । भारत एक पर कानून क्यों अनेक? एक होने चाहिए। हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया है।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : सेंट्रल गवर्नमेंट को यह कानून बनाना चाहिए कि आप भारत के किसी भी प्रदेश में अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यह मेरी गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच।

श्री उपसभापति : श्री शान्ताराम नायक।

श्री रुद्रनारायण पाणि : उस पार्टी के बहुत स्पीकर हैं।

श्री उपसभापति : मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मुश्किल है। टर्न बाई टर्न।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, let me, at the outset, congratulate the first woman President for her exhaustive Address covering the entire facet of India's political and economic scenario. But, Sir, the Address of the first woman President of India was personally attacked by the leader of the Samajwadi Party. It is most unfortunate that the Samajwadi Party leader should attack the first woman President of India saying, "The Address was very weak. उसमें कोई दम नही है।" समाजवादी पार्टी का यह कहना मेरे ख़याल से महिलाओं का अपमान है। राष्ट्रपति की कोई कौम नहीं होती है। But I would like to say that she is a Rajput; she is a brave lady, an intellectual lady, and she has proved, during her tenure, how intelligent and how brave she is. Therefore, I protest the initial insinuation made against the President of India by the hon. Member of the House...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no,...(*Interruptions*) Who said like that?

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: It is there on record...(*Interruptions*) Whatever I said should not be expunged...(*Interruptions*) This is on record of the House. This was also referred to by another hon. Member...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nobody has referred to President in that way...(*Interruptions*) Why do you want to get into controversies? (*Interruptions*)

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) : ये गलत बोल रहे हैं।

श्रीमती जया बच्चन : क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये बिल्कुल सदन को गुमराह कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बोलिए। आप सब्जेक्ट पर आइए।

श्रीमती जया बच्चन : ये हिंदी में बोले हैं। इनको समझ नहीं आया होगा।

श्री अबू आसिम आजमी : शायद आपको हिंदी नहीं आती है।

श्री उपसभापति : आप सब्जेक्ट पर आइए।

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक : सर, मैं सब्जेक्ट पर हूं।

श्री उपसभापति : देखिए I must appreciate that all the hon. Members are cooperating, and let us complete the debate. We have the reply tomorrow. I need more cooperation from the ruling side. आप उसको controversy मत बनाइए प्लीज़ ... **(व्यवधान)** ... मैं कह रहा हूँ। Please proceed further. ...(*Interruptions*)... आप बैठिए।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, to achieve the objectives which are mentioned in the President's Address, we have to have good governance. We need to use the latest technology in order to take governance to the doors of the people. And, e-governance is one of the methods that has to be used by the Government effectively. It is high time that the decisions of the Government are communicated efficiently and ministries in the State and Central Governments use e-governance. We find that when letters are written from departments of the State Government to the Central Government and *vice versa,* replies are received after two or three months. If this system continues, e-governance would have no meaning. Therefore, I strongly urge upon the Government organisations to use e-governance effectively. All replies, even major decisions, must be communicated through electronic means. All notifications of the Government, even Government gazettes, must be posted on the website so that people come to know about it immediately after a decision has been taken. All schemes of the Government must be posted on the website. Even as far as this House is concerned, I would like to make a humble suggestion. We get Unstarred Questions in the lobby after 12; that is all right. If we could get replies to Unstarred Questions through electronic data on the website simultaneously, it will be appreciated. Similarly, replies to Unstarred Questions should also be available on the website so that we can use them effectively and, therefore, the functioning of the House can also improve.

Secondly, the concept of *Gram Nyayalaya,* as referred to by the President, is a laudable one. This concept was there in the olden times also. But if we are introducing the concept of *Gram Nyayalayas* now, then we need to be very, very careful because in the villages, superstitious beliefs still prevail, superstitious beliefs mixed with religious beliefs prevail and, therefore, decisions given by these Panchayat bodies have to be minutely scrutinised. As far as the decisions given by courts are concerned, we can't punish the judges; we can only get the decisions reversed from the higher courts. But as far as decisions given by these *Nyayalyas* are concerned, we have to see to it that, if decisions have been given with malafide intentions, then those Panchayat members are punished.

Now, Sir, in the field of communication, in some areas we are slow and in some areas we are very fast. I would like to refer to Goa specifically. Sir, today, Goa, despite being a State, is being treated as a district. By whom? Not by the Constitution of India, not by the Government of India, but by the Department of Communications which treats Goa as a district. The Department of Communications considers it as a Postal District. The Department

does not consider it a Circle which is equivalent to a State. Sir, the Department of Communications has no right to go against the Constitution which has declared Goa a State. Therefore, I urge upon the Ministry of Communications to declare Goa as an independent Postal Circle, as an independent Telecom Circle, so that we could be at par with Maharashtra. Today, it is considered as a part of Maharashtra. The Department of Communications has merged our State with Maharashtra, which is against the very ethics, the very constitutional verdict, given by the people of Goa.

Then, Sir, as far as the economic zones are concerned, there have been a lot of controversies all over the country. But, it is the State of Goa which has taken effective steps. They have said that they would get even the SEZs which have been notified cancelled in the interests of people. We have urged upon the Commerce Ministry to do so. That is because, in SEZs, they take vast chunks of land, even land which is not required for the purpose of industry, and then use it for urbanisation. Otherwise, why should the builders from Bombay apply for SEZs there? One cannot understand that. Secondly, there is an important lacuna in the SEZ Act. The SEZ Act does not provide that compulsorily employment will be given to the people of the State where the SEZ industries are started. This provision is not there. There is also no provision in the Act to enter into agreement in order to provide jobs to the people of the State compulsorily. Therefore, when we saw this, Sir, we urged upon the Government of India to cancel these SEZs. That is why it has been done. As far as employment is concerned, we can go ahead in other type of industrial units.

Sir, now I would like to talk about the official languages. Sir, development of the people cannot be done through industries and other material things. For development of the people, you have to develop the languages. I would like to say that the Eighth Schedule has been totally neglected. The languages are included in the Eighth Schedule as per the demand of the people. So many languages are there. But, there is no proper policy for the development of these languages. Therefore, the Government of India has to take care of the Eighth Schedule. The Government of India should not be satisfied only by inclusion of these languages in the Eighth Schedule. Even in our House, we don't have regional Interpreters of many languages. There is no Interpreter for my language, i.e., Konkani, in the House, whatever may be the reasons. But the fact remains that there is no Interpreter for Konkani language. Except for three-four languages, Interpreters are not available for other regional languages. So, these aspects have to be taken care of. Sir, I urge upon the Members of the House, who can speak in regional languages, to speak in their regional languages once in each session. Sir, if the Interpreters of regional languages are appointed on regular basis, then, they will have job continuity; otherwise, their jobs will have to be terminated.

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Sir, the hon. Member is...(*Interruptions*)...

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक: अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिन्दी है तो एक बार आप हिन्दी में जरूर बोलिए और अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है तो भोजपुरी में बोलिए ...**(व्यवधान)**

श्रीमती जया बच्चन: मैं बंगाली हूं। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुई एवं बड़ी भी हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में मैंने नाम कमाया और उत्तर प्रदेश की बहू हूं, फिर फलां-फलां जगह मेरी कॉंस्टीट्यूएंसी है, तो अब मैं कौन सी लैंग्वेज में बात करूं।

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक: बंगाली आपकी मातृ-भाषा है, इसलिए उसमें बोलिए ना ...**(व्यवधान)**।

श्री उपसभापति: आप बोलिए-बोलिए, चाहे हिन्दी में बोलिए। आप भारतवासी हैं और भारतवासी की जबान बोलिए ...**(व्यवधान)**

श्रीमती जया बच्चन: आप भाषा के ऊपर देश का विभाजन मत करिए।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Then, Sir, the President's Address has referred to the national highways.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Yes, Sir, I am concluding. The hon. President has mentioned about the national highways. The national highways have to be improved throughout the country. But, at the same time, we have to see that the elements of corruptions are not involved in the expansion and upgradation of national highways. Sir, the National Highway No.17 of Goa has been taken up for upgradation. I urge upon the Government of India that it should be done in the fastest manner.

Then, Sir, I would like to refer to the point relating to Scheduled Tribes. I am mentioning this because recently we have completed the process of delimitation in 22 States. In some other States, there are some problems. But, in Goa, when delimitation came, three communities were notified as Scheduled Tribes, but their figures were not available in the census. It is because when the census was done, these three communities were not declared as Scheduled Tribes. So, we urged upon the Delimitation Commission that since the figures are not available in the Census, you kindly order the Registrar of Census to give you a short Census special figures — they can hold it in two-three months — and reserve for them six-seven seats to which they would have been entitled. But, in spite of that, and despite the Delimitation Commission having the powers under the Delimitation Commission Act, it refused to accept this proposal and did not give the Scheduled Tribes their reserved seats.

There is also no provision in the Delimitation Act for representation of political parties. There is provision for representation of MLAs and MPs, but the political parties are not represented in the Delimitation Commission. This is a major lacuna which is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Naik.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Lastly, Sir, I would like to submit because you are ringing the bell, one more relevant point. All letters which we send as representatives of the people are answered. I cannot say it. Though officially it is answered by the Minister, but they are prepared by some bureaucrats. In 90 per cent cases, if I am not mistaken, they give negative answers. Let a committee be appointed and let it gather 2-3 samples from each Member of Parliament and let that scrutinise those thousand letters and see whether or not there were negative replies even though the work could have been done. Just because of the negative approach of the bureaucracy, the negative replies are given. Even the Ministers are experiencing that. They make announcement of a project. Within two months, an Under Secretary, at the lower level, rejects that proposal in the Ministry owing to technical reasons. I think, addressing this problem is an important aspect in giving a good administration. Thank you very much for giving me the opportunity to speak.

श्री टी.एस. बाजवा (जम्मू और कश्मीर) : उपसभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

सर, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। जो अभिभाषण है, उसमें 68 पैराग्राफ़्स हैं और मैं देख रहा हूँ कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बात करूँगा।

श्री उपसभापति: शुक्रिया।

श्री टी.एस. बाजवा : सर, मैं जम्मू-कश्मीर से आता हूँ। विशेष तौर पर इस अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर के बारे में काफी जिक्र हुआ है। मैं पैरा 57 देख रहा था। "We are committed to peace, friendship and good neighbourly relations with Pakistan". अभी मैडम निर्मला देशपांडे जी ने मेरे से पहले जो बात

कही कि ग्रेनेड से नहीं, गोली से नहीं, बात बनेगी बोली से। इसके लिए मैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की। मुझे याद है कि मैं उस वक्त उस मीटिंग में था, जो वर्ष 2003 में कश्मीर में एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी और जिसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं अपनी दोस्ती का हाथ पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस हाथ को मजबूती से पकड़ेगा। सर, इससे पहले जम्मू-कश्मीर में जो हालात पैदा हुए, लगभग 20 साल से वहाँ मिलिटेंसी रही। जब से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच आपस में वार्ता, bilateral dialogue शुरू किया गया, उसके fruitful results हमारे सामने हैं। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे रास्ते खोले गये हैं, कश्मीर से मुजफ्फराबाद के लिए, पुँछ से रावलाकोट के लिए, यह सिर्फ डिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए है। मैं कहूँगा कि हमारे जम्मू से भी 1947 से पहले जो सुचेतगढ़ से सियालकोट का पुराना रास्ता था, जिस पर ट्रेड होता था, उसको भी खोलना चाहिए। उसका इस अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। उसको खोलना चाहिए, ताकि हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे रिलेशंस मजबूत होंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ डिवाइडेड फैमिलीज़ तक नहीं रहना चाहिए। सर, मैं भी Pak occupied Kashmir से हूँ। 1947 में वहाँ से आने के बाद हमारा बॉर्डर पर resettlement किया गया, तो हम भी यह चाहते हैं। उस वक्त करीब 40 हजार फैमिलीज़ वहाँ से रिफ्यूजी बनकर आईं और जो कठुआ से लेकर उड़ी तक जितना भी हमारा बॉर्डर है, उसके ऊपर उन लोगों को बसाया गया।

सर, जहाँ हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे यू0पी0 के किसान हैं, जो हमारे बाकी प्रदेशों के किसान हैं, उनकी समस्या और जम्मू-कश्मीर के जो किसान हैं, उनकी समस्या अलाहिदा है। अभी हमारे साथी श्री वरिन्दर सिंह बाजवा जी ने जो कहा कि हमारे जम्मू-कश्मीर का जो बॉर्डर है, उसमें से लगभग 6-7 सौ किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1965 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई। 1971 में भी इसी प्रकार हुआ, इसके बाद कारगिल में वार हुई और उसके बाद पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ, तो हमारे जितने भी किसान बॉर्डर पर रहते हैं, जब से हम आजाद हुए हैं, वे पूरे-के-पूरे परेशानी में हैं, हमेशा डिस्टर्ब्ड रहे हैं। 1965 में जब लड़ाई हुई तो एक-एक साल तक हमारा किसान अपना घरबार छोड़कर पीछे आ गया। उसके बाद, ऐसे ही जब 1971 में लड़ाई हुई तो उसको फिर अपना घरबार छोड़ना पड़ा। फिर जब कारगिल में वार हुई, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उससे अभी तक जो हमारा किसान है, उनकी जमीन में अभी तक माइंस लगे हुए हैं। उनको अभी तक उसकी compensation नहीं मिली है। दूसरी सब से बड़ी समस्या यह है कि जो हमारा पूरा बॉर्डर है, उस में infiltration रोकने के लिए तारबंदी की गयी है। उसमें हमारी हजारों एकड़ जमीन फेंसिंग से पार है और हमारे सैकड़ों गांव भी फेंसिंग से पार हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने अभी फैसला किया है कि सरकार 38 किलोमीटर की फेंसिंग को आगे ले जाने का काम कर रही है। इस प्रकार इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे ही जब 1971 की लड़ाई हुई, उस वक्त भी जितना भी हमारा बॉर्डर है, उस मे सबसे आगे फेंसिंग लगी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिच बना हुआ है, उसके पीछे कोई ऐसा गांव नहीं है जिस में आर्मी ने डिफेंस के लिए बंकर नहीं बनाए हैं। लेकिन अभी तक उन किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सर, जहां तक सरकार की बात करें, जैसे मैंने कहा कि यह 68 पैराग्राफ है और भी मैं एक-दो पैराग्राफ पढ़ रहा था जिनमें निर्माण की बात कही गयी है जिसमें नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम में घंटों की बात कही गयी है, नेशनल फूड सेक्युरिटी मिशन की बात कही गयी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कही गयी है और इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपया रखा गया है, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की बात कही गयी है - हम कुल मिलाकर जब इन्हें देखते हैं तो नेशनल रूरल हैल्थ मिशन है जिसमें लगभग 5 लाख के करीब "आशा" इसमें engage किए गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार की एक बहुत बड़ी achievement है। ऐसे ही सर्व-शिक्षा अभियान है।

सर, मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को बधाई

देना चाहता हूं कि पीछे हमारे जम्मू-काश्मीर के कुछ ग्रुप बनाकर राउंड टेबल कांफरेंस की गयी जिसकी सिफारशें आ गयी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो सिफारिशें आई हैं, जो उन्होंने recommendations की हैं, उनके ऊपर पूरा-पूरा अमल होना चाहिए। अभी जो हमारा नेशनल फूड सेक्युरिटी मिशन है, जिसके तहत सरकार ने कहा है कि 10 मिलियन टन paddy की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, 8 मिलियन टन wheat की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा और 2 मिलियन pulses की प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। सर, इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे लिए एम0एस0पी0 फिक्स की गयी है, सबसे पहले हमारी history में ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा प्राइस किसानों को मिल रही है। इसके साथ-साथ जहां wheat की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की गयी है, उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी paddy की जो प्राइस है, वह कम है। इसलिए paddy की प्राइस को बढ़ाना चाहिए।

सर, आखिर में मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। शुक्रिया।

श्री उपसभापति : श्री आर० षण्मुगसुन्दरम - अनुपस्थित। श्री सैयद अज़ीज़ पाशा - अनुपस्थित। श्री कुमार दीपक दास - अनुपस्थित। श्री एन० जोती - अनुपस्थित। श्रीमती प्रेमा करियप्पा।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the President's Address. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So many of your AIADMK friends were waiting, but you were not there. ...(*Interruptions*)... Okay, after that. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, at the outset I should congratulate the hon. President of India for a highly impressive speech covering all sectors and all sections of the society. I also congratulate her, who became the first woman President, for addressing a joint sitting of both the Houses of Parliament. I express my sincere thanks to the UPA Chairperson, Soniaji and also hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji. Sir, reflecting on the UPA Government's perception of the nation, she said that the historic nine per cent growth for the fourth successive year had generated an air of optimism. While taking pride on the "nine per cent growth", the address listed all the programmes aimed at achieving equity and fairness in the developmental process, detailed schemes for the empowerment of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes through increased access to education and the law proposed for the social security for the workers in the unorganised sector. UPA Government's prudent and sound economic management is being highly appreciated. Sir, mentioning that the Government has been paying special attention to the welfare of our farmers and has reversed the decline in public investment in agriculture, the target set in the National Common Minimum Programme of doubling agricultural credit in three years has been substantially exceeded. The Government's firm commitment in ensuring the economic growth process is socially inclusive, regionally balanced and environmentally sustainable by implementing the flagship programmes like Bharat Nirman, aimed at bridging the rural-urban gap in development; the National Rural Employment Guarantee Act to soften the sharp edges of poverty and offer basic livelihood security; Sarva Shiksha Abhiyan, for giving equal opportunity to our children in realising their potential, further strengthened through a universal midday meal programme. The National Rural Health Mission is offering the rural poor access to basic health care. Sir, the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission is promoting socially and economically manageable urban development. All these schemes have been appreciated by one and all. Sir, I congratulate our hon. Chairperson of UPA and our hon. Prime Minister for bringing such good schemes for the development of our country. Sir, her remark on strengthening Panchayati Raj institutions to make the growth process more participatory, responsive and accountable, is highly appreciated. The UPA Government's poverty alleviation programmes

had paved the way for inclusive growth. She emphasized on the Eleventh Plan target that a high growth rate would provide equal opportunities for quality education, health and employment. As a result of better fiscal management, the Centre's contributions to such key sectors has gone up to 50 per cent from one-third in the Tenth Plan period. Sir, the hon. President's priority area was "Empowerment of Women", through female literacy which is our biggest challenge in the social sector. The National Literacy Mission will make acceleration of female literacy as its goal. Sir, the point on foreign policy is highly remarkable, saying the Government seeks to promote an environment of peace and stability in our region and in the world to facilitate accelerated socio-economic development and safeguard our national security. She emphasized on the relations with China, USA, Member States of the EU. Sir, I sincerely thank and heartily congratulate our hon. President of India for her highly impressive and remarkable speech, which covered all the sections and the achievements of the UPA Government. This is a historic Address by the First Woman President of our country. I support the Motion of thanks on the President's Address. Thank you.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I rise to speak in support of the Motion moved by my colleague thanking the hon. President of India for his Address to both the Houses of Parliament. I am really proud, feel elated and also honoured not only because, for the first time, a woman President addressed both the Houses of Parliament but also because of the fact that her candidature was sponsored, supported and proposed by our leader, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, who played a pivotal role in selecting a woman as a candidate for the President of India.

I am a little bit sad...

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Sir, both of us are in a Committee. I am saying that the Chief Minister of Tamil Nadu is going to provide one lady Chief Minister very soon to Tamil Nadu.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Yes. We have a Chief Minister in the making. We have a lady Chief Minister in the making. Don't worry.

Sir, I am sad that it has taken sixty long years for a woman to achieve this high position in the country.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: You should feel happy.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Now, I am happy. But, at the same time, I am sad because it has taken such a long-time.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: You should have hastened it.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: It should have been hastened. Now, I feel, this UPA Government will make it a reality that 33 per cent of women will reach Legislature and Parliament. There will be a reality of this. The DMK will support 33 per cent reservation for women. Sir, the UPA Government was formed after a spectacular win in Tamil Nadu and Pondicherry. In Tamil Nadu and Puducherry, the UPA has got all the 40 seats and my friends in the opposite drew a blank...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): The history will repeat itself again this year ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: It is because of their bad policies. Their policies were totally unfriendly to the people and their Anti-Conversion Bill and their Bill to prevent...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please come to the President's Address.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Those were the reasons. This I have to mention. The reality is that they had lost the election because of anti-people policies...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: What has happened last year?...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, after the Lok Sabha elections, my friends in the Government withdrew all those Bills and there was a sudden roll back and it proves that their policies were totally wrong and against the people.

My friend, the leader of the AIADMK Party, Dr. Maitreyan, was speaking the BJP's voice. He spoke in Hindi to be friendly with the BJP.

DR. V. MAITREYAN: I always speak my Madam's voice.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: I am only warning my friends in BJP that...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Speaking in Hindi does not mean that he is close to the BJP.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: He wanted to make friendship with you.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Hindi is Rashtra Basha.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: I am only cautioning that you better be aware that you will be dropped like a hot potato...(*Interruptions*)...

SHRI SURENDRA LATH: You were also with the BJP.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: We were in the NDA.

श्री सुरेन्द्र लाठ : आप भी BJP के साथ हैं। NDA में आप भी BJP के साथ थे। ..**(व्यवधान)**..

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: You don't forget that 'Tea Party' and what had happened then...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, there is enough material in the President's Address for you to deal with.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I am only attempting to say that the policies of the AIDMK, which were totally unfriendly....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's over. Come to next point.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: When the UPA Government was formed, a document was executed amongst the coalition partners. That set a new trend in the entire coalition *dharma*. It is popularly known as the National Common Minimum Programme. It contained all the policies, which the UPA partners agreed to implement. And, I am very happy that these policies are being implemented. Further, when the UPA Government was formed it was openly announced by the leaders of the UPA and the hon. Prime Minister that there would be a continuance of the policies, particularly people-friendly policies, of the earlier Government. And, they are being implemented. The Indo-US nuclear deal, for instance, was actually proposed and initially discussions were carried out during the NDA Government. That was also continued. I can only recall a recent statement of former diplomat of the United States, Mr. Talbott, who said even if, at that time, half the terms and conditions and the benefits offered to the Agreement at that time, around 2002-03, the then NDA Government would have entered into Agreement. So, that is the situation. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: You could have asked this to Mr. Baalu. He was the Cabinet Minister at that time. Why are you telling this to us. You ask this question to....(*Interruptions*)

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: I am not yielding. (*Interruptions*) Sir, I am also thankful to the former Prime Minister, Shri Vajpayeeji. In 2003, in Chennai, he announced that the *Sethu Samudaram* project would be implemented. Later, for political reasons, they are bringing in Ram or some bridge, which till now not known to them. (*Interruptions*) Now, they are trying to stall this. (*Interruptions*) Sir, these projects have been proposed and discussed for about sixty years in this land. The earlier committees had been formed right from 1950s. Several committees have gone into that. Nowhere these objections were brought in. Even during the NDA Government's rule these proposals were considered. Uma Bharatiji was a Minister at that time, Shatrughan Sinhaji was a Minister at that time, Shri Thirunavakarasu was the Minister of Shipping, Shri Arun Jaitley was the Law Minister. All of them went through the file and passed the proposal. Ultimately, even the sixth alignment, which is now considered, was approved by former Minister, Uma Bharatiji. So, this is the situation. This was also stated in this hon. House by the hon. Minister, Shri T.R. Baalu. When that is the situation, for political reasons certain oppositions are made and unlike the UPA Government, which is. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. Your leader has said everything, Mr. Perumal. (*Interruptions*)

SHRI C. PERUMAL: Because he is in the UPA Government, I request, through you, to solve the Cauvery issue without political...(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now don't come to the Cauvery issue. (*Interruptions*)

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I am very thankful to hon. ...(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : धर्मपाल जी, आप जरा खामोश बैठिए।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: I am very thankful to hon. Shri Perumal. ...(Interruptions)... We are continuing all these people-friendly schemes. ...(*Interruptions*)... Sir, they are taking my time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please help us to go to our houses early.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: The UPA Government is continuing the earlier good policies which are beneficial to the people. Mr. Perumal has just advised that the same should be continued. Sir, in his constituency, the water scheme, that is, the Hogenakal Drinking Water scheme, is being continued and the hon. Chief Minister inaugurated that a week back. ...(Interruptions)... That is what is being done. ...(*Interruptions*)... Sir the UPA Government, when it was formed, withdrew the POTA. ...(*Interruptions*)... Sir, certain comments were made about POTA. Sir, the UPA Government withdrew the POTA because it was proved that this Act was misused in various places. This was also known to the earlier Government. The then hon. Minister, Mr. Arun Jaitley, had introduced two amendments to the POTA Act and appointed the Central Review Committees for that. The Central Review Committees were constituted under the POTA. They scrutinised various cases booked under POTA.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, please conclude now.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, the majority of cases booked in Tamil Nadu were found to be unfit to be prosecuted under the POTA. That was the ruling of the Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please conclude. ...(*Interruptions*)... You have made your points. It is very good. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, the misuse of POTA is also openly known, and, ultimately, the Supreme Court in the case of Vaiko held that use of POTA was totally improper. That is the reason why the UPA Government withdrew the POTA.

SHRI N. JOTHI: The Supreme Court did not say like that. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... Mr. Shunmugasundaram, please conclude now. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: It is not the case of POTA alone, even the earlier TADA Act was misused. Most of the people booked under TADA were also acquitted. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now. ...(*Interruptions*)... I will have to call the next speaker. ...(*Interruptions*)... Please conclude now. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I have 15 minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. ...(*Interruptions*)... Who said you have 15 minutes? ...(*Interruptions*)... You presume that you have 15 minutes. ...(*Interruptions*)... Don't presume like that. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, you said I have 15 minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I never said that.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, earlier you said it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not given more than ten minutes to any of the speakers. Please conclude now.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I will take five more minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I only urge upon the Government that certain other policies should also have been mentioned in this Address. One among them is the reservation benefit to the converts, that is, the Dalits who have been converted from Hindu to other religions, particularly, to Christianity and Islamic faiths. This is being broadly discussed all over the country. We support reservation to such people. This should have been mentioned in the President's Address.

Sir, if you permit me, I will take another five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. ...(*Interruptions*)... Please conclude now. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I now come to the National Rural Employment Guarantee Scheme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody spoke about it.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, my caution is only this. While welcoming that this is being expanded and extended from 330 districts to all the districts in the country, my concern is that there is no proper machinery to monitor and check whether proper payments are made or not. That machinery must be made available and this Government should take care of that. Sir, I welcome ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, they are the Government. ...(*Interruptions*)... What is the UPA Government doing? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may please conclude now.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I am happy ...(*Interruptions*)... Sir, as a Member, I have the right to make my points. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; please conclude now. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, kindly consider giving him time. ..(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, so many interruptions were there. I have sustained so many interruptions. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, you are such a disciplined Member. Earlier, whenever I asked you to conclude, you used to conclude immediately. Why not today? ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, it has been announced that 6500 kilometres of the National Highways are proposed to be made six-lane. Sir, we can see this happening in our country now. We are seeing in Chennai. There are four major flyovers and grid separators are coming up in Kathipara, near airport, and in Padi.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shunmugasundaram, you have also taken up the time you had asked for. Now, please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Yes; yes. ...(*Interruptions*)... Mr. Baalu, is an excellent Minister. ...(*Interruptions*)... He is in-charge of it. ...(*Interruptions*)... Sir, I am only saying that these are all the schemes we are seeing being implemented in this country. With these words, I conclude. (Ends)

श्री उपसभापति : श्री राजनीति प्रसाद , दो मिनट से ज्यादा नही।

SHRI RAJNITI PRASAD (Bihar): Sir, I am thankful to you.

श्री उपसभापति : आप दोनो वेट कर रहे है बहुत देर से, इसलिए ....**(व्यवधान)**...

SHRI RAJNITI PRASAD: Sir, nothing succeeds like success. Ultimately, I succeeded in getting the opportunity to speak on the President's Address.

सर, दो मिनट दीजिए हमको ! सर, सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात हुई है, वह यह है कि वह एक अलग बात है कि हमारी मशीनरी उस तरह की नही है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है, वह उद्देश्य बहुत पाक है और बहुत सफलतापूर्वक सेट्रल गवर्नमेट ने लागू करने का काम किया है। यह बात अलग है कि जो मशीनरी, जहां हमको यह काम फिट करना है, वहां हम ठीक ढग से नही कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा सेट्रल गवर्नमेट ने दिया है। सर, पहले हम लोग रोजी, रोटी कपड़ा और मकान व बेरोजगारो को काम दो, यह नारा लगाते थे। समाजवादी जनसभा मे, लोहिया के नेतृत्व मे, मधु लिमये के नेतृत्व मे हम लोग नारा लगाते थे कि बेरोजगारो को काम दो, तो बेरोजगारो को काम देने की बात एक experiment के तौर पर हो सकती है कि कुछ जिलो के बारे मे कहा गया, कुछ राज्यो को लिया गया था, लेकिन अभी तो ऐसा हुआ कि सारी जगहो पर यह हो जाएगा, सारे जिलो मे यह हो जाएगा, सारे राज्यो में हो जाएगा। ....**(व्यवधान)**....सर, मै यह कहना चाहता हूं कि experiment के तौर पर यह अच्छा काम हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए भी अच्छा काम हुआ है। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है, लेकिन एक बात और है, जनेश्वर मिश्र जी ने जो बात कही है, वह सदन को याद है। वह बहुत रोगटे खड़े करने वाली बात है, उसके लिए भी विचार होना चाहिए।

सर, बहुत ज्यादा बात नही बोलकर, मै केवल एक बात और कहना चाहता हूं। लोगो ने यहां पर कहा है कि महिलाओ का रिजर्वेशन 30 परसेट होना चाहिए। मै कुछ पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं conclude कर दूंगा। मैं पढ़ रहा हूं

"पंचायतो मे महिलाओ के एक-तिहाई आरक्षण के प्रावधान की बदौलत करीब 38 फीसदी निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं है। कर्नाटक मे अनुसूचित जाति-जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधियो की सख्या 65 प्रतिशत और इसी वर्ग की निर्वाचित महिलाओ का प्रतिशत 54 फीसदी है। महिलाओ और कमजोर वर्गों के राजनीतिक सशक्तीकरण की यह मिसाल है। देश की ग्रामीण और शहरी पचायती एव निकाय सस्थाओ मे कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। महिलाओ के आरक्षण का मतलब पार्लियामेट से है - यह आश्चर्य की बात है। यह मै नहीं कह रहा हूं, यह लिखित बात है और भारत मे लोगो को इतनी बड़ी सामाजिक क्राति की जानकारी नहीं है। इतनी सारी महिलाएं चुनकर आयी है। महिलाओ के चुनकर आने का मतलब यह नहीं है कि पार्लियामेट मे जाएं। पचायतो मे और कारपोरेशन मे सब जगह महिलाए चुनकर आ रही हैं। हम लोगो ने कॉंस्टीट्यूशन मे इस तरह से अमेडमेट कर दिया है। यह हमारी उपलब्धि है।

सर, मै एक बात और कहना चाहता हूं। एक बड़ी बात हुई है जिसके सबध मे मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह है - शेडयूल्ड ट्राइब्स ऐड अदर ट्रेडिश्नल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। इस एक्ट के सबध मे मै कहना चाहता हू कि आदिवासियो का विस्थापन न हो और जंगल की जमीन परिवार मे कलह का वातावरण न पैदा करे। 2.5 एकड़ जमीन एक परिवार को उपलब्ध कराने से जमीन के बटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आदिवासी सदियो से जगल मे रहते आ रहे है। उनके अधिकारो का निरतर हनन हो रहा है। जंगल एवं उससे उत्पन्न वस्तुओ के अधिकार को लेकर खनन होने से निरतर विस्थापन हो रहा है, लोग भाग रहे है। इस दिशा मे अभी तक कोई सार्थक प्रयास नही हुआ है। शायद इसी कानून से कुछ बेहतरी की उम्मीद है। यह पैरा मे आया है।

सर, हमारी एक और उपलब्धि है। हम लोग न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, एसडीओ कोर्ट जाते है। वहां लोगो को पैदल चलकर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। इस उपलब्धि का जिक्र पैरा - 18 मे है। हमारी उपलब्धि है कि हम ग्राम न्यायालय भी बना रहे है, जहा पर हमे न्याय मिलेगा। महोदय, मेरा समय नहीं था, फिर भी आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह आप हमे समय देते रहिए। धन्यवाद।

श्री अबू आसिम आज़मी सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ही नही बल्कि मै आपका ऐहसानमद हू कि आपने मुझे वक्त दिया। सर, मै प्रेजीडेट की तकरीर पर बोलने जा रहा हूं। मुझे नही बल्कि मुम्बई के रहने वाले तमाम लोगो को और तमाम उत्तर भारतीयो को इतजार था कि हमारी प्रेजीडेट साहिबा, जो खुशकिस्मती से महाराष्ट्र की रहने वाली है और उत्तर भारत की बहू है, वह प्रेजीडेट बनी हम सबको बहुत खुशी है कि एक खातून, एक महिला बनी है लेकिन मुम्बई मे जो कुछ हुआ, उसके बारे मे कुछ-न-कुछ इसमे आएगा, ऐसा हमे लगता था। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रेजीडेट साहिबा तो जरूर बोलना चाहती होगी लेकिन जिन लोगो ने उनको स्पीच बनाकर दी, उन लोगो की जरूर मुम्बई मे यह सब करवाने की साजिश थी, इसलिए वे लोग इसमे, इस तकरीर मे कुछ नही लाए। मुम्बई एक बहुत बड़ी जगह है। मुम्बई से ही इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। मुम्बई ही है जो सबसे ज्यादा इस देश मे टैक्स देता है। उस मुम्बई मे क्या नही हुआ लेकिन उनकी स्पीच मे कुछ नहीं आया। महोदय, इस स्पीच मे फिल्म इडस्ट्री और बॉलीवुड के बारे मे कहा गया है। इन्होने इस बारे मे कहा है कि बॉलिवुड और फिल्म इडस्ट्री से रोजगार पैदा होता है और फिल्म इडस्ट्री ने भारत का नाम बाहरी मुल्को मे भी ऊचा किया है। हिन्दी फिल्मो से करोड़ो-अरबो रुपए कमाए जा रहे है, लेकिन मुम्बई मे क्या हुआ? मुम्बई मे इतने बड़े स्टेचर के आदमी श्री अमिताभ बच्चन जी के घर पर एक बार नहीं, दो-दो बार हमला होता है। इसी तरह एक भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी जी के घर पर हमला होता है लेकिन उस संबंध मे कुछ नही होता है। उसका कोई जिक्र ही यहा पर नही हो रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है जबकि फिल्म इंडस्ट्री इतना ज्यादा टैक्स देती है, इतना ज्यादा रोजगार देती है - सारे देश के लोग इस संबध मे मुम्बई जाते है, वहा पर ही इससे संबंधित सारा काम होता है।

सर, कौमी यकजहती माहौल के ऊपर कहा है कि बहुत तशवीश की बात है और हमारी सरकार कौमी यकजहती का माहौल बनाएगी। कैसे? मुझे समझ मे नहीं आ रहा है। आज तक श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। यहा तक कि जिनका नाम उसके अदर है, उनको उससे निकाला जा रहा है,

सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि आपको श्रीकृष्ण कमीशन में इम्प्लीकेट नहीं करेंगे। इस प्रकार माहौल खराब होता जा रहा है जिससे इस देश के बीस करोड़ मुसलमानों को ऐसा लगता है कि जो लोग यह कहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमान दूसरे नम्बर का शहरी है, वे ठीक कहते हैं। कॉंस्टीट्यूशन में तो वह बराबर का हक रखता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस मुल्क में कोई हक नहीं रह गया है। सर, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने क्या नहीं किया है। आज एक पूरा परिवार देख रहा होगा, मैं सुबह से आपके सामने बैठा हूं, भीख मांग रहा हूं कि मुझे बोलने दीजिए। सिर्फ इसलिए कि वह परिवार यह आशा कर रहा होगा कि अबू आसिम आज मेरे बारे में बोल देंगे तो शायद मेरा लड़का जेल से छूट जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा लेकिन मैं आपसे यह बोलने के लिए सुबह से यहां पर इसलिए बैठा हूं कि अगर मैं बोल दूंगा तो उसको शायद दिल में तसल्ली हो जाएगी। किस्सा यह है कि 12 दिसम्बर को मौलाना हकीम तारिक इसलाही, जिसकी उम्र 29 साल है, वह आज़मगढ़ का रहने वाला है। देवबंद से मौलाना, मैं इस बात को बड़ी ताकत के साथ कह सकता हूं कि कभी भी कोई मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कूलों, मदरसों में मैंने तालीम हासिल किया है, हमेशा उसमें भाईचारगी का पैगाम दिया गया। एक इंसान को मारना पूरी दुनिया को कत्ल करने के बराबर कहा गया, पूरी इंसानियत को खत्म करने के बराबर कहा गया। वही इंसान बेचारा, जो दिन में तो हकीमी करता है तथा दो घंटे जाकर स्कूल में पढ़ाता है, एक दिन वह बेचारा मोटर साइकिल से जा रहा था। कुछ लोग गाड़ी लेकर आए और उसको उठा लिया। वहां पर औरतें घास काट रही थी, खेत में काम कर रही थी, वे भाग कर आईं और कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो और इस इंसान को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो। तो वे लोग कहने लगे कि नहीं, यह अपनी बीबी से नाराज हो गया है, हम उसकी बीबी के पास इसको घर पहुंचाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसको गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए। फिर उसके बाद लोगों ने समझा कि उसको कोई गुंडे उठा कर ले गए या उसकी किडनेपिंग हो गई है। उत्तर प्रदेश के स्पीकर उसी इलाके के हैं, उनके पास भी लोग गए। स्पीकर साहब ने एस०एस०पी० को फोन किया कि पता लगाओ। इस बारे में डी०एम० के पास, एस०पी०के पास, कचहरी में 10 दिन तक खूब आंदोलन हुआ, तथा अखबार में भी छपा कि उस व्यक्ति की किडनेपिंग हो गई है। एक नेता ने कहा कि अगर पुलिस ने इसका 23 तारीख तक पता नहीं लगाया तो मैं उसी जगह पर जाकर आत्म हत्या कर लूंगा। तो क्या मजाक है, सर, इतनी ज्यादा हठधर्मी कि उस मौलाना के बारे में 22 तारीख को छपता है कि बाराबंकी स्टेशन पर यह आर०डी०एक्स० और बहुत सारे हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ है। यह क्या मजाक है। यानी सबको मालूम है, अखबार में छप रहा है, वहां के उसी कंस्टीट्यूंसी के स्पीकर साहब एस०एस०पी० से पता लगाने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति आर०डी०एक्स० के साथ गिरफ्तार हुआ है। इसका केस कोई वकील लेने को तैयार नहीं हुआ। कहते हैं कि यह दहशतगर्द है तो इसका केस कैसे लेंगे। सर, इसी मुल्क में गांधी जी का मर्डर हुआ, जो पकड़ा गया उस पर मुकदमा चला है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, राजीव गांधी की हत्या हुई है। हत्यारे पर मुकदमा चला, उसके बाद ही फांसी हुई है। उससे पहले नहीं हुई है। मगर वह मुसलमान है। कोई वकील उसका मुकदमा नहीं ले रहा है। बड़ी मेहनत से एक छोटा सा वकील मिला है। उसके बाप दुबई में गुलामों की नौकरी करते हैं, जहां थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। जो दुबई से आकर घर बैठे हुए हैं। बेटे से मिलने गए तो मौलाना रोने लगे और कहा कि अब्बा, वे मुझे पकड़ कर ले गए, एक दिन रात को निकाला, करंट लगाया और फिर अंधेरे में गाड़ी में कहीं ले गए तथा कहा कि हम तुमको मार देंगे, नहीं तो जो कुछ कहते हैं कबूल कर लो। सर, यह मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बात कर रहा हूं। मैं आज इस हुकूमत से कहना चाहता हूं कि बीस करोड़ मुसलमानों को दहशतगर्द कहेंगे तो यह मुल्क कभी आबाद नहीं हो सकता।

श्री रुद्रनारायण पाणि : बीस करोड़ मुसलमानों को दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता है।

श्री उपसभापति : आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो बीस करोड़ मुसलमान हैं उनको कोई उग्रवादी या आतंकवादी नहीं कहता है।

श्री अबू आसिम आज़मी : सर, हम बहुत वाह-वाह लूट रहे हैं, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। हम आज दुनिया में आगे जा रहे हैं, शाइनिंग इंडिया हो रहा है और मुसलमानों के साथ यह क्या हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है। सर, बजट आया मुसलमानों के लिए, कुछ मत दीजिए मुसलमानों को, लेकिन याद रखिए, कम से कम मुसलमानों की जिंदगी तो महफूज रख दीजिए। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी एफ०आई०आर० 14 तारीख को हुई है, और 18 तारीख की रात में एस०टी०एफ० वाले 50 पुलिस वालों को साथ में लेकर उसके घर आ गए, जबकि उसके घर वाले तो उसको ढूंढ रहे हैं। वे आकर कहते हैं कि तुम प्लेन कागज पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे को ढूंढने में आसानी होगी। वे घर में से 248 किताबें लेकर के गए। वे कौन सी किताबें हैं, उनमें कुरान शरीफ है, कुरान की तफसीर है, हकीमी के कागज लेकर चले गए। तो कहा है आतंकवादी किताब। क्या है आतंकवाद, आतंकवादी किताब कौन सी है। गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की इस किताब को आतंकवादी किताब कहा जाता है। जरा यह करक्ट तो करो, यह ऐलान कर के कह दो कि हिन्दुस्तान में कौन सी मुसलमानों की किताब आतंकवादी किताब है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। ...**(समय की घंटी)**

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन क्या हो गई है। मुम्बई जैसी जगह में ...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : बस, अब कंक्लूड कीजिए।

श्री अबू आसिम आज़मी : मैं आपका अहसानमंद हूं, मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति : आपको समय दिया गया है, लेकिन वक्त की पाबंदी है।

श्री अबू आसिम आज़मी : सर, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इतना बोला है, इससे पहले ...**(व्यवधान)**

श्रीमती जया बच्चन : सर, बोलने दीजिए, यह बहुत सीरियस मैटर है।

श्री अबू आसिम आज़मी : मैं सोचता था कि पार्लियामेंट में जो बोलते हैं उस पर सच जवाब आता है। पार्लियामेंट में जो पूछा गया उस पर मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, इस बारे में मुझे बड़ी खुशी थी। लेकिन लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मुझे लिखकर आया कि अब के बार एक्सटेंसन नहीं होगा, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। मैं बड़ा खुश था लेकिन वह टेबल नहीं हुई तथा उसको फिर एक्सटेंशन मिल गई। मैंने सोचा कि शायद एक बार हुआ है। लेकिन फिर एक्सटेंशन हो गया। यह क्या हो रहा है तथा पार्लियामेंट में बोली गई बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों को जबर्दस्ती पकड़ा जा रहा है, आज उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनको जबर्दस्ती टैरोरिस्ट कहा जा रहा है और उनको दस साल, पांच साल जेल में रखकर सब कुछ बर्बाद करने के बाद उनको छोड़ दिया जा रहा है। मुल्क के अंदर यह बंद होना चाहिए। जबकि पोटा कानून खत्म करने की वाह-वाही लूटी जा रही है। पोटा का दूसरा भाई महाराष्ट्र में मकोका लागू हो गया है और मकोका के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि ये सब चीजें, खासतौर से मुम्बई की चीजें और ये सब चीजें नहीं आयी हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। मुसलमानों के साथ जुल्म, ज्यादती बंद होनी चाहिए। हमें मुस्लिम-हिन्दू-सिख-ईसाई सब भाई-भाई रहकर के इस मुल्क की तरक्की करनी चाहिए, यह मेरे दिल की आवाज़ है। अभी कुछ मुसलमानों को मिला नहीं है और अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों का तुष्टिकरण हो रहा है। आपने छाप दिया, लेकिन दिया तो कुछ नहीं, आपने छाप दिया और इन दूसरे लोगों को बोलने का बहाना मिल गया। हमेशा ऐसा ही होता है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है। ...**(समय की घंटी)**...मुझे अफसोस है, यहां तक लिखा हुआ है कि मुसलमान जिस एरिया में रहता है, वहां पर पानी का प्रेशर भी कम है, वहां पर बिजली का कनेक्शन भी कम कर दिया गया है।

श्री उपसभापति : आज़मी साहब, उसके बारे में अलग से गुफ्तगू हो गयी।

श्री अबू आसिम आज़मी : सर, हम आज तो बहुत खुशी मना रहे हैं। ... **(व्यवधान)**... हिन्दुस्तान में यूपीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी वाह-वाह लूट सब लूट रहे हैं और उधर दूसरी तरफ से

मुसलमान बेचारा बगैर कुछ किए हुए जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। ... (समय की घंटी).... मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ बोल रहा हूं कि शायद यह जो कुछ हुआ है, इस पर इन्क्वायरी बैठे और वह गरीब जो बेकसूर है, उसके साथ इन्साफ हो। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

+[**श्री ابو عاصم اعظمی (उत्तर प्रदेश):** सर, आप का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया ही नहीं बल्कि मैं आप का احسان مند ہوں कि आप ने मुझे वक्त दिया। सर, मैं प्रेसिडेंट की तकरीर पर बोलने जा रहा हूं। मुझे नहीं बल्कि ممبئی के रहने वाले तमाम लोगों को और तमाम शमाली भारतियों को इंतजार था कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा, जो खुश किस्मती से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और उत्तर भारत की बहू हैं, वह प्रेसिडेंट बनीं, हम सब को बहुत खुशी है कि एक خاتون, एक महिला बनी है लेकिन ممبئی में जो कुछ हुआ, इस के बारे में कुछ न कुछ इस में आएगा, ऐसा हमें लगता था। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट साहिबा तो जरूर बोलना चाहती होंगी लेकिन जिन लोगों ने उन को स्पीच बना कर दी, उन लोगों की जरूर ممبئی में यह सब करवाने की साजिश थी, इस लिए वह लोग इस में, इस तकरीर में कुछ नहीं लाए। ممبئی एक बहुत बड़ी जगह है, ممبئی से ही इस देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। ممبئی ही है जो सब से ज्यादा इस देश में टैक्स देता है। इस ممبئی में क्या नहीं हुआ लेकिन उन की स्पीच में कुछ नहीं आया।

महोदय, इस स्पीच में फिल्म इंडस्ट्री और बालीवुड के बारे में कहा गया है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि बालीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रोजगार पैदा होता है और फिल्म इंडस्ट्री ने भारत का नाम बाहरी मुल्कों में भी ऊंचा किया है। हिन्दी फिल्मों से करोड़ों अरबों रुपये कमाए जा रहे हैं, लेकिन ممبئی में क्या हुआ? ممبئی में इतने बड़े आदमी श्री अमिताभ बच्चन जी के घर पर एक बार नहीं, दो दो बार हमला होता है। इसी तरह एक भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी जी के घर पर हमला होता है लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं होता है। इस का कोई जिक्र ही यहां पर नहीं हो रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है जबकि फिल्म इंडस्ट्री इतना ज्यादा टैक्स देती है, इतना ज्यादा रोजगार देती है - सारे देश के लोग इस सम्बन्ध में ممبئی जाते हैं, वहां पर ही इस से सम्बन्धित सारा काम होता है।

सर, कौमी यकजहती माहौल के ऊपर कहा है कि बहुत तशवीश की बात है और हमारी सरकार कौमी यकजहती का माहौल बनाएगी, कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तक श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। यहां तक कि जिन का नाम इस के अन्दर है, उन को इस से निकाला जा रहा है, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कि आप को

شری کرشنا کمیشن میں امپلی کیٹ نہیں کریں گے۔ اس پرکار ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے جس سے اس دیش کے بیس کروڑ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان دوسرے نمبر کا شہری ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ کانسٹی ٹیوشن میں تو وہ برابر کا حق رکھتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے اس ملک میں کوئی حق نہیں رہ گیا ہے۔

سر، میں بہت دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا نہیں کیا ہے۔ آج ایک پورا پریوار دیکھ رہا ہوگا، میں صبح سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں کہ مجھے بولنے دیجئے۔ صرف اس لئے کہ وہ پریوار یہ آشا کر رہا ہوگا کہ ابو عاصم آج میرے بارے میں بول دیں گے تو شاید میرا لڑکا جیل سے چھوٹ جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا لیکن میں آپ سے یہ بولنے کے لئے صبح سے یہاں پر اس لئے بیٹھا ہوں کہ اگر میں بول دونگا تو اس کو شاید دل میں تسلی ہو جائے گی۔ قصہ یہ ہے کہ 12 دسمبر کو مولانا حکیم طارق اصلاحی، جس کی عمر 29 سال ہے، وہ اعظم گڑھ کا رہنے والا ہے۔ دیوبند سے مولانا، میں اس بات کو بڑی طاقت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ اسکولوں، مدرسوں میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمیشہ اس میں بھائی چارگی کا پیغام دیا گیا۔ ایک انسان کو مارنا پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر کہا گیا، پوری انسانیت کو ختم کرنے کے برابر کہا گیا۔ وہی انسان بے چارہ، جو دن میں تو حکیمی کرتا ہے تقاضا دو گھنٹے بعد جا کر اسکول میں پڑھاتا ہے، ایک دن وہ بیچارہ موٹر سائیکل سے جا رہا تھا۔ کچھ لوگ گاڑی لیکر آئے اور اس کو اٹھا لیا۔ وہاں پر عورتیں گھاس کاٹ رہی تھی، کھیت میں کام کر رہی تھی، وہ بھاگ کر آئی اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور ان انسان کو کیوں پکڑ کر لے جا رہے ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا ہے، ہم اس کی بیوی کے پاس اس کو گھر پہنچانے کے لئے لے جا رہے ہیں۔ تو اس کو گاڑی میں بیٹھا کر لیکر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ اس کو کوئی غنڈے اٹھا کر لے گئے یا اس کی کڈنیپنگ ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے اسپیکر اسی علاقے کے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ گئے۔ اسپیکر صاحب نے ایس ایس پی کو فون کیا کہ پتا لگاؤ۔ اس بارے میں ڈی ایم کے پاس، ایس پی کے پاس کچہری میں ۱۰ دن خوب آندولن ہوا، تھا اخبار میں چھپا کہ اس شخص کی کڈنیپنگ ہو گئی ہے۔ ایک نیتا نے کہا

کہ اگر پولیس نے اس کا ۲۳ تاریخ تک پتا نہیں لگایا تو میں اسی جگہ پر جا کر آتم ہتیا کرلونگا۔ تو کیا مذاق ہے، سر، اتنی زیادہ ہٹ دھرمی کی اس مولانا کے بارے میں ۲۲ تاریخ کو چھپتا ہے کہ بارہ بنکی اسٹیشن پر یہ آر ڈی ایکس اور بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے۔ یعنی سب کو معلوم ہے، اخبار میں چھپ رہا ہے، وہاں کے اسی حلقہ کے اسپیکر صاحب ایس ایس پی سے پتہ لگانے کے لئے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکتی آر ڈی ایکس کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ اس کا کیس کوئی وکیل لینے کو تیار نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے تو اس کا کیس کیسے لینگے۔

سر، اسی ملک میں گاندھی جی کا مرڈر ہوا، جو پکڑا گیا اس پر مقدمہ چلا۔ اندرا گاندھی کی ہتھیا ہوئی ہے، راجیو گاندھی کی ہتیا ہوئی ہے۔ ہتھیارے پر مقدمہ چلا، اس کے بعد ہی پھانسی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ مگر وہ مسلمان ہے، کوئی وکیل اس کا مقدمہ نہیں لے رہا ہے۔ بڑی محنت سے ایک چھوٹا سا وکیل ملا ہے۔ اس کے باپ دبئی میں غلاموں کی نوکری کرتے ہیں، جہاں تھوڑا بہت کما لیتے ہیں۔ جو دبئی سے آ کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹے سے ملنے گئے تو مولانا رونے لگے اور کہا کہ ابا، وہ مجھے پکڑ کر لے گئے، ایک دن رات کو نکالا، کرنٹ لگایا اور پھر اندھیرے میں گاڑی میں لے گئے تھا کہا کہ ہم تم کو ماردیں گے، نہیں تو جو کچھ کہتے ہیں قبول کرلو۔ سر، یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہا ہوں۔ میں آج اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیس کروڑ مسلمانوں کو دہشت گرد کہیں گے تو یہ ملک کبھی آباد نہیں ہوسکتا۔

شری رُدر نارائن پانی: بیس کروڑ مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہا جاسکتا۔

شری اُپ سبھاپتی: آپ بیٹھئے، ان کو بولنے دیجئے۔

شری رُدر نارائن پانی: سر، میں آپ کا سمان کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے مادھیم سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں جو بیس کروڑ مسلمان ہیں ان کو کوئی اگر وادی یا آتنک وادی نہیں کہتا ہے۔

شری ابو عاصم اعظمی: سر، ہم بہت واہ واہ لوٹ رہے ہیں، ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے۔ ہم آج دنیا میں آگے جا رہے ہیں، شائننگ انڈیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا مل رہا ہے۔ سر، بجٹ آیا مسلمانوں کے لئے، کچھ مت دیجئے مسلمانوں کو، لیکن یاد رکھئے، کم سے کم مسلمانوں کی زندگی تو

محفوظ رکھ دیجئے۔ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایف۔آئی۔آر ۱۴ تاریخ کو ہوئی ہے، اور ۱۸ تاریخ کو رات میں ایس۔ٹی۔ایف۔والے ۵۰ پولس والوں کو ساتھ میں لے کر اس کے گھر آ گئے، جبکہ اس کے گھر والے تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ تم پلین کاغذ پر سائن کر دو تا کہ تمھارے بیٹے کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ وہ گھر میں سے ۲۴۸ کتابوں کو لے کر کے گئے۔ وہ کون سی کتابیں ہیں، ان میں قرآن شریف ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حکیمی کے کاغذ لے کر چلے گئے۔ تو کہاں ہے آتنک وادی کتاب۔ کیا ہے آتنک واد، آتنک وادی کتاب کون سی ہے۔ گورنمنٹ ڈکلیئر کر دے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اس کتاب کو آتنک وادی کتاب کہا جاتا ہے۔ ذرا یہ کریکٹ تو کرو، یہ اعلان کر کے کہہ دو کہ ہندوستان میں کون سی مسلمانوں کی کتاب آتنک وادی کتاب ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔

....(وقت کی گھنٹی)....

میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج لاء اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہو گئی ہے۔ ممبئی جیسی جگہ میں ۔۔مداخلت۔۔

شری اپ سبھاپتی: بس، اب کنکلوڈ کیجئے۔

شری ابو عاصم اعظمی : میں آپ کا احسان مند ہوں، مجھے دو منٹ بولنے دیجئے۔

شری اپ سبھاپتی: آپ کو وقت دیا گیا ہے، لیکن وقت کی پابندی ہے۔

شری ابو عاصم اعظمی : سر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا بولا ہے، اس سے پہلے ۔۔مداخلت۔۔

شریمتی جیہ بچن: سر، بولنے دیجئے، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔

شری ابو عاصم اعظمی: میں سوچتا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو بولتے ہیں اس پر سچ جواب آتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ پوچھا گیا اس پر منتری جی نے جواب دے دیا تو اس کو امپلی مینٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس بارے میں مجھے بڑی خوشی ہے۔ لیکن لبراہن کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں مجھے لکھ کر آیا کہ اب کے بار ایکسٹینشن نہیں ہوگا، لبراہن کمیشن کی ٹیبل کی جائے گی۔ میں بڑا خوش تھا لیکن وہ ٹیبل نہیں ہوئی اور اس کو پھر ایکسٹینشن مل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید ایک بار ہوا ہے۔ لیکن پھر ایکسٹینشن ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور

پارلیمنٹ میں بولی گئی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔

سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن مسلمانوں کو زبردستی پکڑا جا رہا ہے، آج ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو زبردستی ٹیریرسٹ کہا جا رہا ہے اور ان کو دس سال، پانچ سال جیل میں رکھ کر سب کچھ برباد کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ملک کے اندر یہ بند ہونا چاہئے۔ جبکہ پوٹا قانون ختم کرنے کی واہ واہ لوٹی جا رہی ہے۔ پوٹا کا دوسرا بھائی مہاراشٹر میں مکوکا لاگو ہو گیا ہے اور مکوکا کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ سب چیزیں، خاص طور سے ممبئی کی چیزیں اور یہ سب چیزیں نہیں آئی ہیں، یہ سب چیزیں آنی چاہئیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم، زیادتی بند ہونی چاہئے۔ ہمیں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی سب بھائی بھائی رہ کر کے اس ملک کی ترقی کرنی چاہئے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ ابھی کچھ مسلمانوں کو ملا نہیں ہے اور ابھی سے چلانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا تشٹی کرن ہو رہا ہے۔ آپ نے چھاپ دیا، لیکن دیا تو کچھ نہیں، آپ نے چھاپ دیا اور ان دوسرے لوگوں کو بولنے کا بہانہ مل گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ چلا چلا کر کہہ رہی ہے۔ ....(وقت کی گھنٹی)....

مجھے افسوس ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جس ایریا میں رہتا ہے، وہاں پر پانی کا پریشر بھی کم ہے، وہاں پر بجلی کا کنیکشن بھی کم کر دیا گیا ہے۔

شری اپ سبھاپتی: اعظمی صاحب، اس کے بارے میں الگ سے گفتگو ہو گئی۔

شری ابو عاصم اعظمی: سر، ہم آج تو بہت خوشی منا رہے ہیں --مداخلت-- ہندوستان میں یو. پی. اے. سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس کی واہ واہ سب لوٹ رہے ہیں اور ادھر دوسری طرف سے مسلمان بے چارہ بغیر کچھ کئے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہا ہے ....(وقت کی گھنٹی)....

میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں اس امید کے ساتھ بول رہا ہوں کہ شاید یہ جو کچھ ہوا ہے، اس پر انکوائری بیٹھے اور وہ غریب جو بے قصور ہے، اس کے ساتھ انصاف ہو۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The debate will continue tomorrow. The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at twenty-one minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 5th March, 2008.

GMGIPMRND—3017RS—28-01-2009.